संयम ◆संस्कार ◆संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

वर्ष-22 अंक- 304
पृष्ठ 8
शुक्रवार
24 जुलाई 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

शहर समता

प्रयागराज से प्रकाशित Email : shaharsamta@gmail.com Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक–उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध– मानसून में बढ़ जाती है फूड...

विचार– आक्रोश की आड़ में अराजकता का...

खेल– कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत...

994 करोड़ की 14 परियोजनाओं की दी सौगात, बोले–

आस्था पर प्रहार करने वाले अब बने आस्थावान

गोरखपुर,संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे पर गुरुवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 813 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं का लोकार्पण और 181 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी आस्था पर प्रहार करते थे, आज वही आस्थावान बनने का ठेका लेने का दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2007 से 2017 के बीच 10 वर्षों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 29 चीनी मिलों को बंद किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी

पार्टी और कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय और शोषण किया, जिसे प्रदेश की जनता भली–भांति जानती है। उन्होंने कहा कि आज श्नए उत्तर प्रदेशश में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में सड़क संपर्क व्यवस्था पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है और सरकार लगातार आध ारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम कर रही है। गुरुवार को टीपीनगर–पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किमी लंबे सिक्सलेन फ्लाईओवर सहित 813.52 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपये की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के मुंह से आस्था के उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। सपा ने अपने शासन में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन को बाधा पहुंचाई। उसने रामभक्तों पर गोली चलवाई। कांग्रेस ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व और मंदिर आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिवक्ता खड़ा किया। ऐसे लोग आज किस मुंह से आस्था की बात कर रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने अपनी सरकारों में न केवल आस्था से खिलवाड़ किया बल्कि युवाओं को नौकरी और रोजगार से वंचित किया, अन्नदाता किसानों का हक छीना। इन दलों की सरकारों ने बहन–बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा पर संकट खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले यूपी में आए दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। होली, दुर्गापूजा, विजयदशमी, रामनवमी, कृ ष्णजन्माष्टमी जैसे पर्वों पर दंगे होते थे, कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। अब यही लोग आस्था पर बड़े–बड़े हास्यास्पद उपदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले इंसेफेलाइटिस को लेकर सरकारी उदासीनता, सुरक्षा और निवेश के बदतर हालात को लेकर भी कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले इंसेफेलाइटिस बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नियति बन चुकी थी। इसकी चपेट में आकर हजारों बच्चों की मौत हो गई पर तबकी सरकारों के कान पर जूं नहीं रेंगता था। सरकारें कान में रुई डालकर सोई रहती थीं, उन्हें जनता की पीड़ा महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरों और नौजवानों के जीवन के साथ कांग्रेस और सपा ने जितना शोषण और अत्याचार किया उसे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया था। सपा शासन में कभी नौकरी निकली भी तो उस पर उसी पार्टी के लोग युवाओं से छल करते थे। नौकरियों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा हो जाता था।

दोषियों को जल्द सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी सरकार : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने, मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से

यह घोषणा तब की गई है, जब दिल्ली के जंतर–मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में छात्रों–युवाओं का प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह अहम कदम मील का पत्थर साबित होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा, पेपर लीक मामलों में जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का फैसला युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति उनके मजबूत संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है।

मेहनती छात्रों का भविष्य खतरे में डालने वालों को नहीं बख्शा जाएगा : नितिन नवीन

नयी दिल्ली ,एजेंसी। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा कि सरकार देश के युवाओं की उम्मीदों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग मेहनती छात्रों का भविष्य खतरे में डालेंगे, उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। नितिन नवीन ने कहा कि प्रध ानमंत्री ने पहले भी कहा है और अब भी कहते हैं कि वह हर मामले की जांच कराने के लिए तैयार हैं। वह फास्ट–ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। वह यह पक्का करेंगे कि कोई भी दोषी बख्शा न जाए। देश और दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी के संकल्प का मतलब उसे पूरा करना होता है। र पर एक पोस्ट में, नवीन ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार हमारे युवाओं की आकांक्षाओं, कड़ी मेहनत और भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने परीक्षा के पेपर लीक जैसे अपराध ों में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट–ट्रैक कोर्ट बनाने की भी घोषणा की। नबिन ने कहा कि परीक्षा का पेपर लीक होने जैसे अपराधों के खिलाफ तेजी से और कड़ा एक्शन लेने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि दोषियों को तुरंत और कड़ी सजा मिल सके। जो लोग मेहनती छात्रों का भविष्य खतरे में डालते हैं।

पीएम एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के जिम्मेदार : राहुल

नई दिल्ली,एजेंसी। देश भर में नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया किस पेपर लीक मामलों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे 'शिक्षा तंत्र की तबाही' छिपाने की कोशिश करार दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में आरोप लगाया कि देश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रध ानमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर करीब 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाए। राहुल कहा कि नीट पेपर लीक से देश के 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स और उनके परिवार प्रभावित हुए। नीट मामले में किसी भी को सजा नहीं हुई।

महिलाओं के साथ बर्बरता : महिलाओं के साथ पुलिस बदसलूकी करते दिख रही है।

डीसीपी संदीप लांबा पर लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप लग रहे हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल : प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। एक छात्र के शरीर पर बंदूक के छर्रे दिखाई दिए।

पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाला हर व्यक्ति 'पति' नहीं माना जाएगा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहली शादी वैध होने पर दूसरी कानूनन शून्य है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी महिला के संबंध में बीएनएस के तहत धारा 80 (दहेज हत्या) व धारा 85 (क्रूरता) के मामले में 'पति' नहीं माना जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहली शादी वैध होने पर दूसरी कानूनन शून्य है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी महिला के संबंध में बीएनएस के तहत धारा 80 (दहेज हत्या) व धारा 85 (क्रूरता) के मामले में 'पति' नहीं माना जाएगा। हालांकि, यदि पहली शादी को लेकर विवाद या संदेह हो या व्यक्ति ने अपनी पहली शादी की जानकारी छिपाकर दूसरी महिला के साथ वैवाहिक जीवन बिताया तो उसे कानून की नजर में पति माना जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने दिया है। पीलीभीत के माधोटांडा थाने में याची सर्वेश के खिलाफ दहेज हत्या व क्रूरता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि मृतका उसकी दूसरी पत्नी थी और पहली पत्नी विवाह के समय जीवित थी। इसलिए दूसरी शादी शून्य होने के कारण वह बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत 'पति' की श्रेणी में नहीं आता। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वैध विवाह के अभाव में दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में बीएनएस की धारा 80 और 85 के तहत 'पति' नहीं माना जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दूसरी महिला को पहली शादी की जानकारी नहीं थी। व्यक्ति ने अपनी वैध पत्नी को छिपाकर उसके साथ पति के रूप में जीवन बिताया तो वह अपने गलत आचरण का लाभ नहीं उठा सकता। ऐसी स्थिति में उसे धारा–80 और 85 के लिए 'पति' माना जाएगा। कानूनी मुद्दे पर फैसला सुनाने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी सर्वेश को जमानत भी मंजूर कर दी।

पति से वीडियो कॉलिंग के दौरान महिला ने फंदा लगाकर दी जान, भारतगंज में हुई वारदात

प्रयागराज। मांडा थाना क्षेत्र के भारतगंज स्थित कदम रसूल मोहल्ले में बुधवार सुबह एक विवाहिता का फंदे से लटका शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मांडा थाना क्षेत्र के भारतगंज स्थित कदम रसूल मोहल्ले में बुधवार सुबह एक विवाहिता का फंदे से लटका शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के ससुर सलीम ने बताया कि कस्बे के वार्ड चार कदम रसूल निवासी रहमुन निशा (30) पत्नी जावेद ने सुबह करीब 10 बजे अपने कमरे में पति को वीडियो कॉल कर फंदा लिया। यह देख जावेद ने फोन करके छोटे भाई सैफ को जानकारी दी। परिजन भागते हुए छत पर पहुंचे और दरवाजा खोलकर देखा तो वह फंदे से लटकी थी। घटना की सूचना मांडा पुलिस को दी गई। सलीम ने बताया कि घटना के समय वह अपनी दुकान पर थे। घर से सूचना मिलने पर जब वह पहुंचे तो बहू का शव फंदे से लटका था। परिजनों के मुताबिक, रहमुन निशा का मायका मध्यप्रदेश के मऊगंज जनपद के शाहपुर में है। उसका विवाह करीब पांच वर्ष पहले जावेद के साथ हुआ था। जावेद दिल्ली में एक सिलाई कारखाने में नौकरी करता है। मृतका को तीन वर्षीय पुत्र उस्मान और दो वर्षीय पुत्री परी हैं। एसीपी मेजा ब्रजेश पाठक ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों का संकलन किया है।

परिषदीय विद्यालयों के 31,685 सरप्लस घोषित शिक्षक 27 तक दाखिल कर सकेंगे आपत्ति, हाईकोर्ट ने दी मोहलत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात 31,685 सरप्लस घोषित शिक्षकों को 27 जुलाई तक संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में आपत्ति दाखिल करने की अंतिम मोहलत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात 31,685 सरप्लस घोषित शिक्षकों को 27 जुलाई तक संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में आपत्ति दाखिल करने की अंतिम मोहलत दे दी है। स्पष्ट किया है कि सरप्लस घोषित ऐसे शिक्षक जिन्हें सूची में दर्ज आंकड़ों, वरिष्ठता या चयन प्रक्रिया पर आपत्ति है, उन्हें ऑफलाइन आपत्ति जमा करने के बाद उसकी रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही आपत्ति की प्रति बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को स्पीड पोस्ट से भी भेजनी होगी, ताकि उस पर विचार किया जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने चंदौली के सौरभ कुमार सिंह की विशेष अपील पर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिलों से प्राप्त आपत्तियां एक अगस्त तक बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजी जाएंगी। इसके बाद व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। 10 अगस्त से स्कूल, ब्लॉक और जिला स्तर पर संशोधित रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी। सरकार ने आठ अलग–अलग प्रारूपों में सूची जारी कर 31,685 शिक्षकों को सरप्लस चिह्नित किया है। इन शिक्षकों का समायोजन ऐसे विद्यालयों में किया जाना प्रस्तावित है, जहां शिक्षक नहीं हैं या केवल एक है। इसके खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिक्षकों की ओर से दलील दी गई कि कई विद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया जा रहा है, जबकि उनसे जूनियर शिक्षक वहीं तैनात हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि किसी विद्यालय में पिछले पांच वर्षों के भीतर नियुक्त जूनियर शिक्षक कार्यरत हैं तो वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस घोषित किए जाने पर आपत्ति की जा सकती है। वहीं, पांच साल से अधिक समय पहले नियुक्त शिक्षकों के मामलों में फर्स्ट कम, फर्स्ट गो (वरिष्ठता के क्रम) का सिद्धांत लागू रहेगा, जैसा कि एकल पीठ ने अपने 22 मई 2026 के आदेश में निर्धारित किया था।

केंद्रीय कारागार के पास CNG सिलिंडर से लदे डीसीएम में रिसाव

प्रयागराज। केंद्रीय कारागार नैनी के पास बुधवार शाम सीएनजी सिलिंडर से लदे डीसीएम में रिसाव होने लगा। इससे मिर्जापुर राजमार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और नैनी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात को सामान्य किया। केंद्रीय कारागार नैनी के पास बुधवार शाम सीएनजी सिलिंडर से लदे डीसीएम में रिसाव होने लगा। इससे मिर्जापुर राजमार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और नैनी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात को सामान्य किया। बीते आठ जुलाई को औद्योगिक क्षेत्र में भी लीकेज की घटना हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, केंद्रीय कारागार के समीप डीसीएम पहुंचा ही था कि तेज आवाज के साथ सिलिंडर में सीएनजी का रिसाव होने लगा। मालवाहक पर सिलिंडर से सफेद रंग की गैस निकलने लगी।

हाईकोर्ट का अहम फैसला: मातृत्व अवकाश के लिए पहली और दूसरी संतान के जन्म के बीच दो वर्ष का अंतर होना जरूरी नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पहली और दूसरी संतान के जन्म के बीच दो वर्ष का अंतर होना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि किसी महिला कर्मचारी को सेवा नियमों के तहत दूसरी संतान के लिए मातृत्व अवकाश का अधिकार प्राप्त है, तो केवल दो वर्ष का अंतराल न होने के आधार पर उसका अवकाश आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मातृत्व अवकाश के लिए पहली और दूसरी संतान के जन्म के बीच दो वर्ष का अंतर होना जरूरी नहीं है। इस आधार पर किसी महिलाकर्मी को अवकाश देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कानपुर नगर निवासी स्टाफ नर्स शिखा यादव व एक अन्य की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से याची को मातृत्व अवकाश दिए जाने से इन्कार करने वाले छह व नौ जनवरी के आदेश का रद्द कर दिया। याचियों की मातृत्व अवकाश की अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उत्तर प्रदेश वित्तीय हैंडबुक के नियम 153(1) और आठ दिसंबर 2008 के शासनादेश के अनुसार पहले मातृत्व अवकाश के दो वर्ष के भीतर दूसरा मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश वित्तीय हैंडबुक की कार्यपालिका संबंधी व्यवस्था संसद के बनाए गए सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020 के प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकती। संहिता की धारा–161 स्पष्ट करती है कि यदि किसी अन्य कानून, नियम या कार्यपालिका के निर्देश उससे असंगत हैं तो संहिता के प्रावधान प्रभावी होंगे। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020 में पहली और दूसरी संतान के जन्म के बीच किसी न्यूनतम समय अंतराल की शर्त नहीं है। इसलिए केवल दो वर्ष का अंतर न होने के आधार पर किसी महिलाकर्मी को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को याचियों की अर्जी पर दो हफ्ते में नए सिरे फैसला लेने का आदेश दिया है।

दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ छात्र संगठनों का हल्लाबोल, निकाला आक्रोश मार्च

प्रयागराज। दिल्ली पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में दिशा छात्र संगठन के आह्वान पर बुधवार को आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च अल्लापुर सब्जी मंडी से शुरू होकर बक्शी बांध, नागवासुकि मंदिर होते हुए बालासन चौराहे तक पहुंची।

दिल्ली पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में दिशा छात्र संगठन के आह्वान पर बुधवार को आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च अल्लापुर सब्जी मंडी से शुरू होकर बक्शी बांध, नागवासुकि मंदिर होते हुए बालासन चौराहे तक पहुंची। मार्च को संबोधित करते हुए संगठन के प्रियांशु ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों की मांगों पर संवाद करने के बजाय बल प्रयोग किया गया। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे व छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए सरकार से माफी की मांग की। संगठन के अनुसार, प्रदर्शन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए।

दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी व अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पत्थर गिरिजा घर धरना स्थल से सिविल लाइन सुभाष चौराहा तक आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन छात्रों और नेता राहुल गांधी के साथ प्रशासन व सत्ता पक्ष की ओर से की गई कथित बर्बरता और दमनकारी नीतियों के विरोध में आयोजित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शेखर बहुगुणा ने छात्रों की जायज मांगों और

नेता राहुल गांधी के साथ हो रहे अन्याय व दुर्व्यवहार के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया।

अल्पसंख्यक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरशद अली ने कहा कि यदि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना अपराध है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग की।

इस मौके पर तस्लीम उद्दीन, आबदी हसन, मो. हसीन, मनोज पासी, शकील अहमद, गजली खान, नरेंद्र गिरी, मो जाहिद आदि मौजूद रहे। वहीं, एनएसयूआई ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदर्श सिंह भदौरिया ने कहा कि जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी की गई और छात्रों–युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर आघात है।

दिल्ली कूच कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने किया नजरबंद

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाप्रदर्शन के लिए दिल्ली कूच कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने गंगापार जिला अध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन पुलिस को सौंपा और सरकार विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली कूच के लिए मंगलवार की शाम सिकंदरा स्थित इकट्ठा हो गए।

जानकारी होने पर थानाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अशफाक अहमद समेत सभी कांग्रेसियों को नजरबंद कर दिया। इस मौके पर देवराज उपाध्याय, साधुचरण तिवारी, सुनील पांडेय, डॉ.जगत नारायण सिंह, सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. अमर सिंह पटेल, निशा सिंह, विनोद तिवारी, मंजू मौर्या, अफजाल अहमद आदि रहे। उधर, मंसूराबाद में अपनी जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एलबी पटेल को दिल्ली के जंतर–मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने से पूर्व पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया।

सात दिन से लापता इंटर की छात्रा का यमुना में मिला शव, नए पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी की आशंका

प्रयागराज। करछना के सुलमई गांव निवासी 12वीं की छात्रा मानसी (22) का शव सात दिन बाद बुधवार को मनकामेश्वर मंदिर के पीछे यमुना नदी में उतराता मिला। वह 16 जुलाई को कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी।

करछना के सुलमई गांव निवासी 12वीं की छात्रा मानसी (22) का शव सात दिन बाद बुधवार को मनकामेश्वर मंदिर के पीछे यमुना नदी में उतराता मिला। वह 16 जुलाई को कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी। जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई। पुलिस के अनुसार, शव करीब दो दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस प्रथम दृष्टया नए यमुना पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या की आशंका जता रही है, हालांकि सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कीडगंज पुलिस का कहना है कि छात्रा ने जान क्यों दी, परिजन इस बात को छिपा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मानसी एक सप्ताह से घर से लापता थी। परिजनों का कहना है कि वह अक्सर झूंसी स्थित अपनी

बड़ी बहन की ससुराल चली जाती थी। 16 जुलाई को घर नहीं लौटने पर लगा कि झूंसी चली गई होगी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी। अब शव मिलने पर परिवार के लोग अनहोनी की आशंका जाहिर करने लगे।

कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस

प्रयागराज। 12वीं की छात्रा मानसी 16 जुलाई को घर से निकली थी जबकि उसका शव सात दिन बाद यमुना में मिला। ऐसे में सवाल यह है कि घर से निकलने के बाद वह पांच दिनों तक कहां रही और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। कीडगंज पुलिस के मुताबिक, 12वीं के बाद मानसी ने इसी वर्ष क्षेत्र के एक कॉलेज में स्नातक में प्रवेश लिया था। उसके पिता के शराब पीने की बात भी सामने आई है। परिजनों के अनुसार, मानसी की देखभाल ननिहाल में मामा करते थे। घटनास्थल से छात्रा का मोबाइल फोन भी मिला।

ऐसे में अब जांच का फोकस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल, सीडीआर, संभावित लोकेशन, कॉलेज और परिचितों से पूछताछ, साथ ही नए यमुना पुल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज पर रहेगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के कारण और घर से निकलने के बाद की पूरी कड़ी स्पष्ट हो सकेगी।

आजाद प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन

प्रयागराज। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे देश के छात्रों और नौजवानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बृहस्पतिवार नागरिक समाज, दिशा और आइसा समेत कई संगठनों ने चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंचकर आजाद को उनकी जयंती पर नमन किया और लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया।

मशरूम के पाउडर से तैयार किया ऑर्गेनिक फेस पैक, मिला पेटेंट

प्रयागराज। चौधरी महादेव प्रसाद (सीएमपी) डिग्री कॉलेज के वैज्ञानिक ने त्वचा में निखार लाने के लिए मशरूम के पाउडर से ऑर्गेनिक फेस पैक तैयार किया है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। चौधरी महादेव प्रसाद (सीएमपी) डिग्री कॉलेज के वैज्ञानिक ने त्वचा में निखार लाने के लिए मशरूम के पाउडर से ऑर्गेनिक फेस पैक तैयार किया है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। जंतु विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. हेमलता पंत व उनकी टीम के इस शोध को सरकार ने पेटेंट दे दिया है। जल्द ही यह उत्पाद बाजार में नजर आएगा। इसके लिए विभिन्न कंपनियों से बात चल रही है। इस शोध को पूरा होने में दो साल लगे हैं। यह नवाचार हर्बल एवं प्राकृतिक कॉस्मेटिक उत्पादों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह फेस पैक त्वचा को निखारने के साथ उसकी प्राकृतिक सुरक्षा और मरम्मत में भी सहायक होगा।

यह फेस पैक मशरूम में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कई जैव–सक्रिय यौगिकों पर आधारित है। इनमें बीटा–ग्लूकान, एर्गोथायोनीन, फेनोलिक यौगिक पॉलीसैकराइड्स, बी–कॉम्प्लेक्स विटामिन और विभिन्न खनिज तत्व शामिल हैं। डॉ. हेमलता पंत के अनुसार, ये तत्व त्वचा को एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करते हैं। मुक्त कणों से होने वाली क्षति को कम करने में मदद कर सकते हैं। शोध में यह पाया गया कि फेस पैक त्वचा की नमी बनाए रखने, सूजन कम करने और त्वचा की प्राकृतिक मरम्मत की प्रक्रिया को समर्थन देने में उपयोगी है। इसके अतिरिक्त यह कोलेजन निर्माण को बढ़ावा देने में भी सहायक है। इससे त्वचा अधिक स्वस्थ, मुलायम और चमकदार दिखाई दे सकती है।

प्राकृतिक और पर्यावरण–अनुकूल उत्पाद

डॉ. हेमलता पंत ने बताया कि यह उत्पाद पूरी तरह प्राकृतिक एवं पर्यावरण अनुकूल अवधारणा पर आधारित है। इसमें ऐसे घटकों का उपयोग किया गया है जो जैविक रूप से सुरक्षित माने जाते हैं। पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हैं। यह नवाचार हर्बल कॉस्मेटिक उद्योग को नई दिशा देने के साथ टिकाऊ उत्पादों के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।

धरने से पहले सपा नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, तैनात रही भारी फोर्स

प्रयागराज। बहरिया क्षेत्र के सारी पट्टी में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विकास निगम के नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के विरोध में दादूपुर–करनाईपुर संपर्क मार्ग पर धरना प्रदर्शन और जुलूस प्रस्तावित था।

बहरिया क्षेत्र के सारी पट्टी में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विकास निगम के नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के विरोध में दादूपुर–करनाईपुर संपर्क मार्ग पर धरना प्रदर्शन और जुलूस प्रस्तावित था। सूचना मिलने पर बहरिया पुलिस मौके पर पहुंची और धरना प्रदर्शन की पूर्व अनुमति न होने के कारण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी।

पुलिस ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित कई सपा नेताओं को उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आवास के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि दिल्ली के जंतर–मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में क्षेत्र में जुलूस निकाला जाना था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। बहरिया थाना प्रभारी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। संबंधित पक्ष ने अनुमति नहीं ली थी, इसलिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, 80 वर्षीय बुजुर्ग बरी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के एक पॉक्सो मामले में करीब 80 वर्षीय स्वामी दीन को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने 10 दिसंबर 2025 को उन्हें पॉक्सो मामले में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के एक पॉक्सो मामले में करीब 80 वर्षीय स्वामी दीन को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने 10 दिसंबर 2025 को उन्हें पॉक्सो मामले में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज कराने में पांच दिन की देरी का अभियोजन पक्ष संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। मूल एफआईआर में यौन अपराध का आरोप नहीं था, जबकि बाद में गंभीर धाराएं जोड़ी गईं। पीड़िता की मां के बयान में विरोधाभास हैं। इससे बच्ची को सिखाए–पढ़ाए जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा–164 के बयान में भी पहचान और घटना के समय को लेकर गंभीर विसंगतियां मिलीं। चिकित्सा और फॉरेंसिक साक्ष्य से अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर पॉक्सो मामलों में साक्ष्य सर्वोत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए। इसी के साथ संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने दोषसिद्धि रद्द कर आरोपी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

कन्फर्म टिकट पर अब अपने सामान की भी ऑनलाइन कर सकेंगे बुकिंग

प्रयागराज। ट्रेन में कन्फर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में ले जाने वाले निर्धारित वजन तक के व्यक्तिगत सामान (लगेज) की बुकिंग भी ऑनलाइन करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने इस पारदर्शी व्यवस्था को पूरे देश में 31 जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया है। ट्रेन में कन्फर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में ले जाने वाले निर्धारित वजन तक के व्यक्तिगत सामान (लगेज) की बुकिंग भी ऑनलाइन करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने इस पारदर्शी व्यवस्था को पूरे देश में 31 जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (क्रिस) की ओर से तैयार किए गए इस विशेष सॉफ्टवेयर के जरिये यात्रियों को स्टेशन पर लगेज बुकिंग की लंबी औपचारिकताओं और कतारों से मुक्ति मिलेगी।

संक्षिप्त

विधायक आलम बदी का निधन, विधानसभा अध्यक्ष ने व्यक्त किया गहरा शोक

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के 90 वर्षीय वयोवृद्ध विधायक आलम बदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री महाना ने अपने शोक संदेश में कहा कि आलम बदी का निधन प्रदेश की राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और जनकल्याण के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। अध्यक्ष ने दिवंगत पुण्यात्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों, समर्थकों एवं उनके असंख्य शुभचिंतकों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में 7 लाख की चोरी, शटर उखाड़कर घुसे चोर

लखनऊ (संवाददाता)। काकोरी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपये का सामान चुरा लिया। टिकरिया मोड़ स्थित बहरू रोड पर राधा–कृष्ण मार्केट में विश्वजीत इलेक्ट्रॉनिक्स नामक दुकान को निशाना बनाया गया। पीड़ित दुकानदार विश्वजीत के अनुसार, चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत करीब सात लाख रुपये है। बदमाश दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और दर्जनों महंगे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा। उसने शटर टूटा और दुकान के अंदर सामान बिखरा हुआ पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही काकोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाए। चोरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। उन्होंने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि बहरू रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर इतनी बड़ी चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल पीड़ित दुकानदार की ओर से अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है।

आउटर रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा, रॉन्ग साइड आए डंपर ने ट्रश्वला में मारी टक्कर

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में किसान पथ (आउटर रिंग रोड) पर गुरुवार तड़के डंपर और ट्रॉला में भीषण टक्कर हो गई। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जिससे लंबा जाम लग गया। राहगीरों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। यह घटना खुशहालगंज के पास गुरुवार तड़के करीब 4 बजे हुई। बताया गया कि डंपर गलत दिशा में आ रही थी। उसने ट्रॉला में टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के बाद का डंपर चालक निर्मल निवासी कानपुर मौके से फरार हो गया। दूसरे वाहन का चालक भी दुर्घटनास्थल से चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पर दी। सूचना मिलने पर पीआरवी टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पारा थाना पुलिस काफी देर तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जबकि हादसे के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। हादसे की जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की एंबुलेंस और हाईवे गश्ती दल भी मौके पर पहुंचा। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने के लिए हाइड्रा और जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। वाहनों को हटाने के बाद मार्ग साफ कराया गया, जिसके बाद यातायात धीरे–धीरे सामान्य हो सका। फिलहाल, इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं हुई है। दोनों वाहन चालकों को मामूली चोट लगने की बात सामने आई है। दोनों फरार हैं।

निर्माणाधीन अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से 4 मजदूर गिरे,पाइप टूटने से हुआ हादसा

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में गुरुवार को निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सातवीं मंजिल पर प्लास्टर का काम कर रहे चार मजदूर पाइप टूटने से नीचे गिर गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही महानगर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत–बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं। घायलों को तत्काल पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तहसीलदार सदर जय प्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह कार्य के दौरान पाइप का टूटना सामने आया है। अब तक चार मजदूरों के घायल होने की पुष्टि हुई है। वहीं मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल (एमडीआरवी) की रेस्क्यू टीम ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एफएसओ हजरतगंज रामकुमार रावत ने बताया कि सातवीं मंजिल पर प्लास्टर का काम चल रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। चारों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल किसी मजदूर की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। घायल मजदूरों का इलाज नीरा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। प्रशासन हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रहा है।

68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन

लखनऊ (संवाददाता)। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में शामिल अभ्यर्थियों ने गुरुवार को भजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने उनसे मांग करते हुए कहा की राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 68,500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत पर परिणाम संशोधित करा कर नई सूची जारी करें। इस भर्ती का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया की 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने एवं सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की संस्तुति की गई है।

कलेक्ट्रेट परिसर में मनाई गई अमर बलिदानी चन्द्रशेखर आज़ाद की 120वीं जयंती

प्रतापगढ़ (आर.एन.एस.)। कलेक्ट्रेट परिसर में अमर बलिदानी चन्द्रशेखर आज़ाद की 120वीं जयंती श्रद्धा, सम्मान एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं साहित्यकार श्री राजकिशोर त्रिपाठी ने की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि श्री श्याम शंकर शुक्ल श्श्यामश रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री विनोद कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। अतिथियों ने अमर शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

अपने उद्बोधन में वक्ताओं ने कहा कि चन्द्रशेखर आज़ाद का त्याग, साहस, स्वाभिमान एवं राष्ट्रप्रेम आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। आज के युवाओं को उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर सम्मानित मंच पंडित चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण भी किया साथ ही चन्द्र शेखर आजाद की स्मृतियों को जनपद के मूर्धन्य साहित्यकारों ने अपनी कविताओं के माध्यम से साझा किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार श्याम जी ने माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए आजाद की याद में अपनी पंक्तियां पढ़ी यह जननी जन्मभूमि की पावन वसुंधरा है, मेरा वतन चमन है सदैव हरा भरा है।

अध्यक्षता कर रहे अधिवक्ता राज किशोर त्रिपाठी नेपढ़ा –मैं भी देखता हूं मन के सुनहरे सपने, जल्दी ही पूरे होंगे ये इरादे अपने। आजाद महाकाव्य के रचयिता प्रेम कुमार त्रिपाठी प्रेम ने महाकाव्य की पंक्तिया कुछ इस तरह से पढ़ा – गोरों की ताकत को रौंदा देकर बहुत बड़ा संदेश। शिखर हिमालय चढ़ ललकारा हिंदुस्तान हमारा देश।।

सुरेश संभव ने पढ़ा –इन्ही को पूजने पंक्तियां कलम से उतर रही। युगों युगों से कल्पना इन्हें प्रणाम कर रही।। अमित शुक्ल अमित ने भारत वन्दना करते हुए पढ़ा – भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा।। संचालक सुरेश नारायण दुबे व्योम ने पढ़ा– राष्ट्र सुरक्षित होगा तब ही हम सकुशल रह पाएंगे ,

प्रदीप चतुर्वेदी ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि आजाद देश के लिए ऐसा काम कर गए हैं जिसके लिए देश आजन्म उनका ऋणी रहेगा

इस अवसर पर दीपक पांडे नीतेश त्रिपाठी सिनोद सिंह तैयब अली राम आसरे बाल गोविन्द अवनीश विनय विश्वकर्मा वपौधरोपण में जनपद में ख्याति अर्जित कर रहे अरुण ओझा,परशुराम सेना के अध्यक्ष प्रदीप शुक्ल की गरिमामयी उपस्थिति रही

अंत में उपस्थित सभी जनों ने अमर शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद के आदर्शों को आत्मसात करने तथा राष्ट्रहित में सदैव समर्पित रहने का संकल्प लिया।

जिलाधिकारी से आज मिलेंगे सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर

भयहरण नाथ धाम की सुव्यवस्था, सावन मेला व बकुलाही नदी पुनरोद्धार पर होगी वार्ता

प्रतापगढ़। प्रसिद्ध पांडव कालीन बाबा भयहरण नाथ धाम के महासचिव एवं प्रबंधक समाज शेखर आज जिलाधिकारी महोदय से कलेक्ट्रेट चौम्बर में मुलाकात करेंगे। इस भेंट में धाम की सुव्यवस्था, आगामी सावन मेला की तैयारियों की प्रगति, 15 मार्च से चल रहे सामाजिक सत्याग्रह के समाधान, तथा बकुलाही नदी पुनरोद्धार अभियान के अवशेष सरकारी कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में संवाद कर समाधान हेतु आग्रह किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष भयहरण नाथ धाम क्षेत्रीय विकास संस्थान के अध्यक्ष राज कुमार शुक्ल, कोषाध्यक्ष लाल जी सिंह , उपाध्यक्ष प्रशासन बबन सिंह, उपाध्यक्ष वित्त राजीव नयन मिश्र, सचिव, संगठन राज किशोर मिश्र , बकुलाही नदी पुनरोद्धार अभियान– उप संयोजक मोती लाल चौधरी , जिला प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन अंबावता– मो. जलालुद्दीन शामिल है। बकुलाही नदी पुनरोद्धार अभियान के संयोजक समाज शेखर ने कहा कि धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और क्षेत्र के विकास व बकुलाही पुनरोद्धार के लिए प्रशासन से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है।

राष्ट्रभक्ति, त्याग और साहस की अमर गाथा है चंद्रशेखर आजाद का जीवन-केशव

लखनऊ (संवाददाता)। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सरकारी आवास, 7–कालिदास मार्ग पर महान क्रांतिकारी, अद्वितीय पराक्रम, अदम्य साहस और अटूट राष्ट्रभक्ति के प्रतीक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर उनके स्मृति–चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा विनम्र नमन किया। उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का त्याग, शौर्य और मातृभूमि की स्वतंत्रता के प्रति उनका अटूट समर्पण भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उनका संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित रहा और उन्होंने अपने अद्वितीय साहस, अदम्य आत्मबल तथा राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा से स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की। उनका प्रेरणादायी जीवन प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान और संघर्ष के कारण ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। आज का भारत उनके सपनों के अनुरूप एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। देश का प्रत्येक नागरिक उनके आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय जनता पार्टी देश के सभी महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, संतों, समाज सुधारकों और राष्ट्रनिर्माताओं का समान भाव से सम्मान करती है तथा उनके बताए आदर्शों और मूल्यों को जन–जन तक पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी गौरवशाली विरासत, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान देने का कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहा है। गर्व का विषय है कि वर्ष 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश स्थित भाभरा चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली का दौरा

करने वाले पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। यह उनके महान क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान, राष्ट्रवादी विचारधारा और स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रमाण है।श्री मौर्य ने कहा कि आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी चंद्रशेखर आजाद के राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, त्याग और साहस से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और जनसेवा को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाएं।

अविमुक्तेश्वरानंद बोले, यूपी में रावण राज जैसा माहौल, श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजा

लखनऊ (संवाददाता)। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 81 दिन की गविष्ठि (गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध) यात्रा के दौरान उनके और उनके समर्थकों को कई जगह परेशान किया गया। लखनऊ में प्रस्तावित गौ गर्जन अक्षौहिणी संकल्प कार्यक्रम को प्रशासनिक परिस्थितियों के चलते अब डिजिटल माध्यम (वर्चुअल) से आयोजित करने का फैसला लिया गया है। शंकराचार्य ने दावा किया कि यात्रा के दौरान कई स्थानों पर उन्हें रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं दी गई। हमें रात में सड़क पर समय बिताना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 जुलाई के कार्यक्रम में आने वाले कई कार्यकर्ताओं को उनके घरों में ही रोक दिया गया है। कुछ लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी जा रही है और कई जगह बिजली तक काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब अभी भी हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, जबकि हमें कार्यक्रम की अनुमति मिली हुई है। शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि यहां रावण राज आ चुका है। उन्होंने कहा कि पहले 24 जुलाई को आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति उपवन में दोपहर 12 बजे गौ गर्जन अक्षौहिणी संकल्प का सार्वजनिक आयोजन होना था, लेकिन अब इसे प्रत्यक्ष की बजाय डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच गौ माता की रक्षा को लेकर संकल्प और आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी है। यात्रा का उद्देश्य गौमाता की रक्षा के लिए जनजागरण करना था। यात्रा के दौरान प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संवाद किया गया। यात्रा के दौरान उन्हें प्रदेशभर में लोगों का समर्थन मिला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर परिसर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने बयान पर भी सवाल उठाए।

आया जब सैलाब

(कुण्डलिया)

उम्मीदों को रौंदकर, आया जब सैलाब।
ख़्वाब उड़न छू हो गए, ज़हर बन गया आब।
ज़हर बन गया आब, परेंशा प्राणी दिखते।
छत बिन हुए मकान, खुले में हैं सब रहते।
सुन लो कहें प्रदीप, छोड़कर तरकीबों को।
हरियाली से आज, जोड़ लो उम्मीदों को।।

बेकाबू नदियाँ हुईं, पानी करे विनाश।
बादल के पीछे दिखें, जब पूरा आकाश।
जब पूरा आकाश, हुआ अब जीना दूभर।
डूब रहे हैं गाँव, शहर भी हुआ समन्दर।
सबकुछ देख प्रदीप, कह रहे सुन लो बाबू।
करो वृक्ष से प्रेम, न काटो हो बेकाबू।।

डॉ. प्रदीप चित्रांशी
लूकरगंज, प्रयागराज

पेपरलीक से लेकर राम, मंदिर चढ़ावा विवाद तक भ्रष्टाचार की देन : मायावती

लखनऊ (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपरलीक पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। कहा कि पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन का मुद्दा अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दे रहा है। उन्होंने आंदोलन के राजनीतिकरण पर चिंता जताई। कहा कि सरकार और आंदोलनकारियों को इसका शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। टकराव से किसी समस्या का हल नहीं हो सकता।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दिल्ली के जंतर–मंतर पर काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन उन छात्र–छात्राओं और उनके परिवारों की पीड़ा से जुड़ा है। ये लोग नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपरलीक और अन्य गड़बड़ियों से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक हंगामे की स्थिति बनी हुई है। अब इस आंदोलन का राजनीतिकरण होने से मामला सरकार के साथ सीधे टकराव की दिशा में बढ़ गया है। इसका असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न राज्यों में भी सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बसपा प्रमुख ने कहा कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और अखिल भारतीय व राज्यों की परीक्षाओं में पेपरलीक की घटनाओं के पीछे मूल कारण भ्रष्टाचार है।

हर स्तर पर पनप रहा भ्रष्टाचार ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा है। इससे आम जनता का विश्वास सरकारों के प्रति कमजोर पड़ रहा है। मायावती ने इसे संवैधानिक नैतिकता से भी जुड़ा गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता पर विशेष बल दिया था। लेकिन इसके अभाव में भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है।

उत्तर मध्य रेलवे

ई-टेण्डर नं. पी आर वाई जे-सिग-022-2026-27 दिनांक: 21.07.2026

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से वरि0 मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियन्ता/समन्व0/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज द्वारा ई-टेण्डर के द्वारा पर्याप्त वित्तीय क्षमता एवं अनुभव सहित प्रतिष्ठित ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के लिये **खुली निविदा**, ई-निविदा में वर्णित खुलने के दिनांक को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।

निविदा नं.: 022	अनुमानित मूल्य : ₹ 2,94,61,884.59
कार्य का विवरण: प्रयागराज मंडल के वरि0 मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियन्ता/सिग0 के अनुभाग में स्टेशनों एवं रिले हटों गेटों पर स्थापित/एसएमपीएस आधारित स्टेटकान माडल के आईपीएस प्रणालियों के दो वर्षों की अवधि हेतु व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध।	
बिड सिक्यूरिटी : ₹ 589200.00	निविदा प्रपत्र का मूल्य : ₹ 0.00
कार्य समापन की अवधि : चौबीस माह	निविदा खुलने की तिथि : 18.08.2026

निविदा प्रपत्रों की उपलब्धता: निविदा प्रपत्र www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। **धरोहर की राशि जमा करना एवं उसका रूप:** निविदाओं को उपरोक्त बिड सिक्यूरिटी निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन भुगतान गेटवे द्वारा की जायेगी। यदि निविदा वाला बिड सिक्यूरिटी उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में जीसीसी के अनुसार जमा करते हैं तो उनका निविदा स्वीकार किया जायेगा। यदि निविदाकर्ता द्वारा जमा की गयी बिड सिक्यूरिटी बैंक गारंटी के रूप में है तो यह उचित स्टांप शुल्क के अनुसार होना चाहिये। बैंक गारंटी जमा करते समय यह 3080 स्टांप अधिनियम 2008 की धारा 13 एवं 24 और समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होना चाहिये। बिना बिड सिक्यूरिटी वाली निविदायें खारिज कर दी जायेंगी। **निविदा खुलने का समय तथा स्थान:** निविदा पूर्व निर्धारित तिथि 12.30 बजे या उसके बाद ई-निविदा द्वारा मण्डल रेल प्रबंधक, प्रयागराज के कार्यालय में खोली जायेगी। अगर उस दिन किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहे तो निविदा अगले दिन, कार्य दिवस पर खोली जायेगी। **निविदा की वैधता:** निविदा खुलने के 60 दिन तक। **निविदा डीलिंग हेतु रेलवे के अधिकार:** रेलवे प्रशासन का, किसी भी समय बिना कारण बताये कोई एक या सारी निविदाओं को स्थगित/संशोधित/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। 1673/26 (A)

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

उत्तर मध्य रेलवे

(इलेक्ट्रिकल कोचिंग ब्रांच)

ई-निविदा सूचना सं. ई टी-71/विद्युत/कोचिंग-प्रया0/2026-27 दिनांक- 21.07.2026

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता (कोचिंग) उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज निम्नलिखित कार्य के लिए निर्धारित फार्म पर E-Tender दिनांक 12.08.2026, समय 15.00 बजे तक आमंत्रित करते हैं। निविदा के सम्बन्ध में मुख्य सूचनायें निम्नवत् है:-

निविदा संख्या: ETCHG-71	कार्य की लागत (रू0 में): रु. 1,15,58,255.92
कार्य का नाम: प्रयागराज मंडल की मौजूदा वॉशिंग लाइन में फ्लडलाइट, पिट लाइट्स तथा अन्य संबंधित कार्यों का प्रावधान एवं सुधार।	
धरोहर राशि (रू0 में): रु 2,31,200.00	समयावधि: 06
टेण्डर फार्म की कीमत (रू0 में): NIL	निविदा खुलने की तिथि: 12.08.2026
निविदा का प्रकार: कार्य (खुली निविदा) कैपिटल आवंटन	

नोट:- 1. उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.ireps.gov.in पर समय 15:00 बजे टेण्डर खुलने की तिथि तक उपलब्ध है। 2. उपरोक्त निविदा में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप से बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेन्डरों को चाहिए कि वे अपने आपको I.T. Act-2000 के अन्तर्गत CCA द्वारा जारी Digital हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। 3. निविदा की दरें केवल डिजिटल हस्ताक्षरित फाइनेंशियल रेट पेज पर ही विचारणीय हैं। दरें तथा अन्य वित्तीय प्रभार अन्य किसी भी फार्म/लेटर हेड पर यदि संलग्न हैं तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सीधे तौर पर अमान्य कर दिया जायेगा। 4. संलग्न किये जाने सभी प्रपत्र निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिये। 5. निविदा सूचना को निम्नलिखित वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। a) www.ncr.indianrailways.gov.in 6. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए IREPS की वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। 7. ईएमडी का भुगतान केवल ऑनलाइन कई बैंक की नेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए। 8. **पात्रता मानदण्ड- निविदा सं. ETCHG-71 के लिए** (क) निविदाकर्ता ने इनमें से किसी एक को सफलतापूर्वक पूरा किया होना या पर्याप्त रूप से पूरा किया होना पिछले 07 (सात) वर्षों के दौरान काम की निम्नलिखित श्रेणियां, पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त करना एक जिसमें निविदा आमंत्रित की जाती है- कम से कम तीन समतुल्य कार्य, जिसकी लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 30% से कम न हो। या कम से कम दो समतुल्य कार्य, जिसकी लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 40% से कम न हो। या कम से कम एक समतुल्य कार्य, जिसकी लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 60% से कम न हो। 'समतुल्य कार्य' की परिभाषा इस प्रकार है- कार्य के संतोषजनक निष्पादन से मतलब है- **"HT/LT इंस्टॉलेशन से जुड़े किसी भी इलेक्ट्रिकल काम को संतोषजनक ढंग से पूरा करना।** (ख) निविदाकर्ता का न्यूनतम औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार वी/एन या वी जो कम हो, जहाँ पे वी = निविदा का विज्ञापित मूल्य करोड़ रुपये में एन = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 'कुल संविदात्मक भुगतान' के औसत के रूप में की जाएगी, लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार। तथापि, यदि पिछले वर्ष की तुलन-पत्र अभी तक तैयार लेखापरीक्षित नहीं है, तो औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना के लिए चौथे पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र पर विचार किया जाएगा। निविदाकर्ता अनुबंध-VIB के अनुसार अपेक्षित जानकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों की प्रतियों/लेखापरीक्षित तुलन-पत्र द्वारा समर्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र की प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेंगे। (ग) निविदाकार के पास (ओईएम को छोड़कर यदि वे स्वयं सम्मिलित हो रहे हों।) वैध विद्युत लाइसेंस होना चाहिए। 1672/26 (K)

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @CPRONCR

सम्पादकीय.....

कचरे का संकट

यह हमारी व्यवस्था की विडंबना ही है कि सड़कों व सार्वजनिक स्थलों में पसरा कचरा हटाना हमारी प्राथमिकता नहीं बनता। यह कचरा केवल दिखने में ही बुरा नहीं लगता बल्कि कई तरह के रोगों को जन्म देकर सार्वजनिक संकट का कारक भी बन सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण सफाई का काम करने वाला वर्ग आर्थिक व सम्मान की दृष्टि से सबस ज्यादा उपेक्षित रहता है। कमोबेश पंजाब की सड़कों पर जमा कचरा यही संकट दर्शा रहा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच घातक बीमारियां फैलने के खतरे को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चेतावनी यह बताती है कि शहरी जीवन के लिये मूलभूत नागरिक सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। खासकर मानसून के सीजन में यदि कचरा नहीं उठाया जाता तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। बारिश में इस कचरे के बहने से नालियां जाम हो जाती हैं। वहीं पानी के स्रोत भी दूषित हो सकते हैं। साथ ही मच्छर,चूहे व कीट–पतंगे पनपने से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट का राज्यभर की नागरिक संस्थाओं से रिपोर्ट मांगना और सरकार की जवाबदेही तय करना वक्त की जरूरत भी है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि नगर निकायों के अधिकारियों को जरूरी सेवाओं, विशेषकर लोगों की सेहत से सीधे जुड़ी सेवाओं के लिये आपातकालीन योजनाएं बनानी ही चाहिए। निस्संदेह, इस संकट को महज कानून व व्यवस्था के नजरिये से ही नहीं देखा जा सकता। निर्विवाद रूप से हमारे समाज में सफाई कर्मचारियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस अहम कार्य को हम अपेक्षित मान्यता नहीं देते। यह विडंबना ही है कि सफाई कर्मचारी लंबे समय से नौकरी की असुरक्षा, स्थायी होने में लगने वाली देरी, मिलने वाला कम वेतन और काम करने की खराब स्थितियों की शिकायत करते रहते हैं। शोचनीय स्थिति यह है तंत्र सफाई कर्मचारियों की मांगों को तब तक नजरअंदाज करता है, जब तक वे अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों में नहीं उतर जाते। बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सफाई कर्मचारियों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। लेकिन हड़ताल व स्वास्थ्य सेवाओं का ठप होना न तो लोगों के हित में है और न ही सफाईकर्मियों के हक में। भारत में हर रोज 1.7 लाख टन से ज्यादा ठोस कचरा विभिन्न नगरपालिकाओं के अंतर्गत पैदा होता है। लेकिन तीव्र गति से बढ़ते शहरीकरण के चलते नागरिक सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में इस चुनौती के मुकाबले के लिये आधुनिक तकनीक के साथ प्रोफेशनल तरीके से ठोस कचरे का निस्तारण होना चाहिए। साथ ही जरूरी है कि पर्याप्त स्टाफ मिले, सफाई के आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाएं। इसके अलावा इस क्षेत्र में निरंतर निवेश बढ़ाया जाए। हमारे नीति–नियंताओं को सोचना चाहिए कि आपातकाल के समय की गई कोई भी कार्रवाई लंबी अवधि की योजना का विकल्प नहीं बन सकती। ऐसे में सरकार के अधिकारियों को तुरंत सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। उनकी जायज मांगों को एक तय समय सीमा में हल करने की दिशा में अविलंब काम करना चाहिए। इसके अलावा आपातकालीन इंतजामों के जरिये साफ–सफाई से जुड़ी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहनी चाहिए। निस्संदेह, किसी भी तरह के विवाद के चलते आम लोगों की सेहत को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। यह भी विडंबना ही है कि जब तक सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जमा होना शुरू नहीं होता, तब तक अक्सर शहरों की सफाई को हल्के में ले लिया जाता है। निश्चित रूप से हाल ही में पंजाब में पैदा हुए गतिरोध से हमें सबक लेना चाहिए। बल्कि इस चुनौती के बीच साफ–सफाई को एक जरूरी जन सेवा के तौर पर मान्यता देने का उपक्रम करना चाहिए। हमारा प्रयास हो कि हम शहरों की सफाई के लिये बेहतर नियोजन करें। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफाई के काम से जुड़े लोगों के कार्य का महत्व समझते हुए उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया जाए। नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

आक्रोश की आड़ में अराजकता का एजेंडा!

बालकृष्ण थरेजा

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहनशीलता है। यहां असहमति को सम्मान मिलता है, विरोध को स्थान मिलता है और सरकारों से सवाल पूछना नागरिक का अधिकार माना जाता है। लेकिन लोकतंत्र की यही शक्ति तब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, जब विरोध और अराजकता के बीच की लक्ष्मण रेखा जानबूझकर धुंधली कर दी जाए। दिल्ली के जंतर–मंतर पर हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर यही प्रश्न खड़ा किया है कि क्या देश में हर जनभावना को राजनीतिक संघर्ष का औजार बनाने की परंपरा मजबूत होती जा रही है? इसमें कोई विवाद नहीं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की अव्यवस्था ने लाखों युवाओं का धैर्य तोड़ा है। वर्षों तक कठिन परिश्रम करने वाले अभ्यर्थी, कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग दिलाने वाले माता–पिता, बार–बार स्थगित होती परीक्षाएं, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं का वर्षों तक अदालतों में उलझना और समय पर नियुक्तियां नहीं मिलना, ये सब ऐसे घाव हैं, जिनकी पीड़ा को कोई भी संवेदनशील समाज नकार नहीं सकता। देश का युवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि अपने भविष्य की निश्चितता मांग रहा है। उसकी यह मांग पूरी तरह न्यायसंगत है और सरकार का दायित्व भी है कि वह परीक्षा प्रणाली में जनता का भरोसा हर कीमत पर बहाल करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या युवाओं की इसी वास्तविक पीड़ा को कुछ राजनीतिक और वैचारिक समूह अपने–अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे? जंतर–मंतर का घटनाक्रम केवल विद्यार्थियों के आक्रोश तक सीमित दिखाई नहीं दिया। वहां जिस प्रकार की राजनीतिक सक्रियता, उत्तेजक भाषण और टकराव का वातावरण देखने को मिला, उसने स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न खड़े कर दिए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है लेकिन कानून लागू कराने वाली पुलिस को खुलेआम चुनौती देना, उसके विरुद्ध भीड़ को उकसाने वाली भाषा का प्रयोग करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकता। आज दुर्भाग्य यह है कि देश में कोई भी बड़ा मुद्दा सामने आते ही कुछ स्थायी चेहरे हर आंदोलन में दिखाई देने लगते हैं। विषय बदल जाते हैं, नारे बदल जाते हैं लेकिन मंच पर मौजूद चेहरे शायद ही बदलते हों। कृषि कानूनों का आंदोलन हो, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध, अग्निवीर योजना का विवाद या अब प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न, हर बार वही राजनीतिक और वैचारिक समूह सबसे आगे दिखाई देते हैं। यह भी कम चिंता की बात नहीं कि सोशल मीडिया अब किसी भी आंदोलन का सबसे प्रभावशाली हथियार बन चुका है। कुछ सैकेंड के वीडियो, चुनिंदा दृश्य, भावनात्मक संगीत और आक्रामक टिप्पणियां कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती हैं। पूरे घटना का संदर्भ पीछे छूट जाता है और एक भावनात्मक नैरेटिव आगे आ जाता है। इसलिए केवल सरकार ही नहीं, मीडिया, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। यदि राजधानी में इतने बड़े स्तर पर भीड़ जुटी और प्रशासन उसकी गंभीरता का समय रहते आकलन नहीं कर पाया, तो यह खुफिया तंत्र की कमजोरी मानी जाएगी। यदि समय रहते संवाद स्थापित किया जाता और आवश्यक तैयारी होती, तो शायद हालात इतने तनावपूर्ण नहीं बनते। लेकिन सरकार की इस कमी का अर्थ यह भी नहीं कि कानून–व्यवस्था को चुनौती देने वालों को खुली छूट दे दी जाए। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। यदि भीड़ नियंत्रण से बाहर जाने लगे, यदि पुलिस पर दबाव बनाने या उसे उकसाने का प्रयास किया जाए, तो कार्रवाई करना प्रशासन का दायित्व बन जाता है। संविधान नागरिकों को प्रदर्शन का अधिकार देता है लेकिन किसी को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कानून अपने हाथ में लेने या समाज में अराजकता फैलाने का नहीं। सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि इस पूरे घटनाक्रम में वास्तविक मुद्दा कहीं पीछे छूटता दिखाई दिया। चर्चा इस बात की कम हुई कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी कैसे बनाया जाए, पेपर लीक कैसे रोके जाएं, भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध कैसे हों और युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। इसकी बजाय बहस सरकार और विपक्ष के टकराव तक सिमट गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों विद्यार्थियों को होगा, जिनके नाम पर यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। समय की मांग है कि सरकार परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करे, पेपर लीक करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करे, भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध बनाए और न्यायिक विवादों के त्वरित समाधान का रास्ता निकाले। युवाओं की पीड़ा पर राजनीति करने से किसी का भविष्य नहीं बनता। रोजगार का रास्ता नारे नहीं, नीतियां बनाती हैं। यदि विरोध व्यवस्था को तोडने लगे, यदि आक्रोश राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हथियार बन जाए और यदि युवाओं के सपनों का इस्तेमाल सत्ता संघर्ष के मंच के रूप में होने लगे तो सबसे पहले लोकतंत्र ही घायल होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश का युवा राजनीतिक मोहरा नहीं, राष्ट्रीय प्राथमिकता बने। सरकार से जवाबदेही भी मांगी जाए और कानून का सम्मान भी किया जाए। यही लोकतंत्र की मर्यादा है, यही संविधान की भावना है और यही भारत के भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता भी।

प्रधानमंत्री मोदी के लिए अच्छे संकेत नहीं

जंतर–मंतर से संसद तक कूच का ऐलान तो 20 जुलाई के लिए किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ जैसा सलूक किया, उसके बाद 21 जुलाई को फिर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी न केवल जंतर–मंतर पर जुटे, बल्कि नागपुर में संघ मुख्यालय के सामने से लेकर और कई शहरों में अपनी नाराजगी के साथ उतरे। अब प्रदर्शनकारियों की मांग केवल धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रह गई है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सब के इस्तीफे की मांग हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच कर ही उनके इस्तीफे की मांग की, जो हालिया राजनीति में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम है। किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन, महिला पहलवानों का धरना, विपक्ष के प्रदर्शन सब मंचों से उठती विरोध की आवाज को कुचलने का रवैया मोदी सरकार का रहा है। लेकिन इस बार शायद सभी हदें पार हो गई हैं, इसलिए विरोध भी अब शांत होने की जगह और बढ़ गया है। सोमवार को सरकार ने प्रदर्शनकारियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। लड़कियों, स्कूल जाने वाले बच्चों तक को अपनी लाठियों का निशाना बनाया। लाठी चलाने के भी कुछ उसूल होते हैं, जैसे पैरों पर मारना, ताकि प्रदर्शनकारी को चोट भी पड़े, लेकिन जान को खतरा न बने। लेकिन यहां मोदी सरकार ने 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में पहुंचे जनरल डायर की भयावह याद ताजा करवाई, जिसने देखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, फिर भी निकलने का एकमात्र रास्ता बंद करवा कर पुलिस से गोलियां चलवाईं। सोमवार को भी संसद प्रवेश द्वार पर बंदूकें तैनात किए हुए सुरक्षाकर्मी खड़े थे। बस गोली चलाने की कसर थी। हालांकि गोली चलती तो साफ दिखता कि सरकार की तरफ से चलाई गई है। इसलिए डायर से भी ज्यादा चालाकी से काम लिया गया। सोशल मीडिया पर खबरें आई हैं कि कई बैरिकेड्स में करंट दौड़ाने की खबर है, ताकि कुछ प्रदर्शनकारी घायल हों या मरें तो यह दुर्घटना की तरह दिखे। पुलिस वालों की तरफ से पत्थर चलाने और लड़कियों–बच्चों को मारने, कुछ लोगों के नाजुक अंगों पर प्रहार की तस्वीरें भी सामने आई हैं। चालाकी का एक और उदाहरण यह है कि पुलिस वर्दी पहने कई लोगों के नाम का बैच वर्दी पर नहीं लगा था, यानी यह पता ही नहीं है कि मारने वाले वाकई पुलिसकर्मी थे या उनके भेस में कोई गुंडे। रविवार की रात जिस तरह जंतर–मंतर के बाहर पत्थर से लदे ट्रक और टूटी गाड़ियां खड़ीं थी, वो सारे मामले को और संदिग्ध बना रही हैं। आज तक यह भी तो साफ नहीं हो पाया है कि गोधरा में उसी बोगी में आग कैसे लगी थी, जिसमें कारसेवक थे और उसके बाद वह आग कैसे पूरे गुजरात को जला गई। जिन लोगों ने ऐसी भयावह साजिश रचकर समाज को बांट डाला, वो और क्या कुछ कर सकते हैं, इसका अनुमान क्या आम इंसान कभी लगा पाएगा। जवाब ना में ही होगा। अपने उज्ज्वल भविष्य की चिंता करने वालों पर ऐसा अत्याचार जो सरकार करे, उसे एक पल भी सत्ता में और रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन निर्लज्जता देखिए कि सोमवार को लोकतंत्र के लिए एक और काला दिवस बना देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एनडीए सांसदों के साथ मंगल–मिलन किया। ऐसे सांसदों पर लानत भेजनी चाहिए जिन्हें ऐसे आयोजन में शिरकत करने लज्जा न आई, बल्कि किरण रिजीजू जैसे मंत्री ने बाहर निकलकर कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा देने का निश्चय किया है। उन्होंने दोबारा पेपर भी करवाए। मंत्री जी को लगे हाथ ये भी बता देना चाहिए था कि मंगल–मिलन में जब मोदी पेपर लीक पर बात कर सकते हैं, तो यही बात उन्हें सदन में विपक्ष की मौजूदगी में करने में क्या हर्ज है। क्या अब मंगल–मिलन की बैठकें लोकसभा की आधिकारिक कार्यवाही के तौर पर दर्ज होंगी। मंगलवार सुबह ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मिला था और सोमवार के घटनाक्रम पर अपनी चिंता दर्ज कराते हुए सदन में चर्चा की मांग की थी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। यही सब करने के लिए तो भाजपा दूसरे दलों को तोड़कर संसद में अपना संख्या बल बढ़ाने में लगी है। अब जनता का एक बड़ा वर्ग अफसोस मना रहा है कि उसने भाजपा को वोट दिया, अब टीएमसी, शिवसेना या एनडीए का साथ देने वाले दूसरे दलों को वोट देने वाले भी पछता ही रहे होंगे। हालांकि अब देश का माहौल जिस तरह मोदी सरकार के खिलाफ बन गया है, उसमें अब भाजपा के साथ खड़े होने वालों को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत अब भी नहीं है और 243 सीटें विपक्ष के पास हैं, टीएमसी, शिवसेना सांसदों की बगावत के बाद आंकड़ा कुछ और कम हो सकता है, लेकिन गैर–भाजपाई सांसद संविधान और लोकतंत्र का लिहाज करते हुए विचार करें तो 272 का जादुई आंकड़ा इस पाले से उस पाले में जा सकता है। बहरहाल, सत्ता परिवर्तन अभी दूर की कौड़ी लग रही है, पर राजनीति में असंभव शब्द भी तो नहीं है। दरअसल जिस तरह से नरेन्द्र मोदी इस देश को चला रहे हैं, उसमें अब कमजोर, पीड़ित, दमित जनता के लिए इंसाफ की गुंजाइश कम होती जा रही है। मंगलवार को ही जब दिल्ली हाईकोर्ट में लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका दर्ज कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई, तो इस मांग को खारिज करते हुए जवाब मिला कि हमें इसमें मत घसीटिए। अब आम अवाम अदालत में इंसाफ की गुहार न लगाए तो कहां लगाए। घूम–फिरकर उम्मीद विपक्ष पर ही जा टिकती है। सोमवार को समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने जिस तरह कई घायल प्रदर्शनकारियों का ख्याल रखा, उनके लिए पुलिस से भिड़ गईं, वो वीडियो खूब वायरल हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय राउत समेत बाकी विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को इस मामले में खूब घेरा। और मंगलवार को यह देखकर अच्छा लगा कि श्रीनिवास बी वी के नेतृत्व में कांग्रेस सेवादल के लोग भोजन–पानी–दवाइयों के साथ प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गए। इधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राममनोहर लोहिया अस्पताल जाकर घायल प्रदर्शनकारियों से मिले। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर मोबाइल नंबर भेजा ताकि जिन्हें मदद की जरूरत हो, वो सीधे संपर्क कर सकें। विपक्ष ने दिखा दिया कि वह केवल सरकार की आलोचना के लिए नहीं बैठा है, आंदोलनकारियों की मदद भी कर रहा है। इस पूरे आंदोलन का सूत्रपात कॉकरोच जनता पार्टी ने किया, लेकिन सोमवार को अभिजित दिपके उस समय वाहन के अंदर बैठे थे, जब प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चल रही थीं। गनीमत है कि वे मंगलवार को फिर से जंतर–मंतर पर बैठे थे, सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया की तरह बर्गर खाने नहीं निकल गए थे।

क्या यह मोदी राज के अंत की शुरूआत है?

राजेंद्र शर्मा

सड़कें अगर खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है! जनतंत्र के भारतीय अभ्यास से निकली इस जानी–मानी कहावत के हिसाब से संसद के मानसून सत्र के पहले के दिन, 20 जुलाई के संसद मार्च ने, जो प्रचंड रूप से युवाओं का संसद मार्च साबित हुआ, संसद और वास्तव में तो सरकार के नकेल डालने के जनतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी काम की शुरूआत कर दी है। सरकार और उसके सारे तंत्र के ही नहीं, खुद इस मार्च का आह्वान करने वालों के भी सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए, लाखों की संख्या में छात्र, युवा और अन्य जनतंत्र की परवाह करने वाले सुबह से ही इस संसद मार्च में शामिल होने के लिए जंतर–मंतर की तथा संसद की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर जमा हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि परंपरागत अर्थ में मार्च जैसा कुछ व्यवस्थित प्रयास संभव ही नहीं था क्योंकि हर तरफ लोग ही लोग थे। और थे असाधारण रूप से बड़ी संख्या में पुलिस बल। और जहां यह उल्लेखनीय है कि यह विशाल जनसमूह, परंपरागत अर्थों में चाहे राजनीतिक नहीं हो, फिर भी जंतर–मंतर पर महीने भर से जारी मुसलसल धरने तथा तीन हफ्ते से जारी प्रख्यात शिक्षाविद, वैज्ञानिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता, सोनम वांगचुक और वामपंथी छात्रों की भूख हड़ताल के जरिए उठाए जा रहे मुद्दों के साथ काफी मुखर तथा आवयविक जुड़ाव के चलते, पूरी तरह से अनुशासित तथा शांतिपूर्ण था, वहीं यह भी उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्द्ध–सैनिक बलों की सारे हरबे–हथियारों के साथ सामान्यतरू डरावनी तैनाती का, युवाओं की इस फौज के मन में शायद ही कोई डर था। इसी का नतीजा था कि जब अमित शाह के निर्देश पर पुलिस बलों ने आंसू गैस के गोलों से लेकर, लाठी चार्ज के नाम पर सैंकड़ों निहत्थे प्रदर्शनकारियों की घेर कर बर्बर पिटाई तक के जरिए, इस विशाल जनसमूह को तितर–बितर कर भगाने की कोशिश की, उसने राजधानी में संसद पर किसी भी प्रदर्शन पर सबसे भीषण दमनचक्र का रिकार्ड तो बना दिया, जिसमें सौ से ज्यादा घायल तो राजधानी के सिर्फ दो केंद्र सरकार के अस्पतालों में ही उपचार के लिए भर्ती कराए गए थे। इनमें एक छात्रा की हालत तो इतनी खराब है कि उसे वेंटीलेटर पर रखा जा रहा है। लेकिन, यह सारा दमनचक्र भी जंतर–मंतर, कनॉट प्लेस तथा संसद के गिर्द के शेष इलाके को देर रात तक भी, प्रदर्शनकारियों से पूरी तरह से खाली नहीं कर पाया। यहां तक कि धरने के जिस मुख्य मंच को तथा उसके नजदीक के वामपंथी छात्र संगठनों के उप–मंचों को, प्रदर्शनकारियों पर अपनी चढ़ाई के क्रम में पुलिस पूरी तरह से तोड़–फोड़ दिया था और इलाके पर अपने पूरे कब्जे का ऐलान कर दिया था, देर शाम तक वहां एक बार फिर प्रदर्शनकारी जमा हो चुके थे और मंच की फौरी मरम्मत के साथ, धरने के जारी रहने की घोषणा की जा चुकी थी। इससे पहले, सोनम वांगचुक की संसद मार्च पर पुलिस दमन के खिलाफ अस्पताल में अपना आमरण अनशन आगे जारी रखने की घोषणा आ चुकी थी। देर रात को सीपीआई (एम) महासचिव, एमए बेबी समेत कई नेता व सांसद भी वहीं धरने में शामिल होकर, धरने की निरंतरता पर मोहर लगा चुके थे। दूसरी ओर, जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, मानसून सत्र के पहले ही दिन, दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने जोर–शोर से युवाओं की मांगों के और उनके संसद मार्च पर बर्बर पुलिस दमन के मुद्दों का उठाया। और जैसाकि मोदी राज में कायदा ही बन गया है, सरकार ने तथा उसके इशारे पर सभापतियों ने इस मुद्दे पर फौरन चर्चा कराने से इंकार कर दिया, पहले ही दिन संसद की कार्रवाई इस हंगामे के चलते बार–बार स्थगित करनी पड़ी। एक और संबंधित घटना विकास में, जिसमें बहुत ज्यादा अर्थ पढ़ना शायद अभी जल्दबाजी ही होगी, जंतर–मंतर पर महीने भर से चल रहे धरने तथा भूख हड़ताल के अस्तित्व और युवाओं के आंदोलन को मोदी सरकार ने कम से कम पहचाना तो सही। मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व–भाजपा अध्यक्ष, जेपी नड्डा से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और उन्हें मार्च का पांच सूत्री मांगपत्र दिया। सभी जानते हैं कि इस मार्च का आह्वान, नीट पर्चा लीक सहित केंद्रीयकृत परीक्षाओं में गड़बड़ियों समेत, विशेष रूप से सार्वजनिक शिक्षा की बढ़ती दुर्दशा की जिम्मेदारी के प्रतीक में रूप में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जंतर–मंतर पर महीने भर से जारी, धरने की ओर से किया गया था। धरने के दूसरे सप्ताह से सोनम वांगचुक तथा वामपंथी छात्र नेताओं के भूख हड़ताल शुरू करने से आंदोलन में और तेजी आई। प्रधान के इस्तीफे समेत एनटीए के भंग किए जाने आदि पांच मांगों को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर–मंतर पर जारी धरने की ओर से एक मांगपत्र भी जारी किया गया था, जिसे व्यापक समर्थन मिला। वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई, आईसा तथा एआईएसएफ, छात्रों–युवाओं के सबसे ज्वलंत मुद्दों को विचार के केंद्र में लाने के प्रयास की अभिव्यक्ति के रूप में, इस नवगठित पार्टी के आंदोलनात्मक कार्यक्रम के साथ शुरूआत से ही जुड़े रहे थे, जबकि युवाओं, मजदूरों, किसानों, महिलाओं आदि के जनसंगठनों की एकजुटता उसे हासिल रही थी। नीट पेपर लीक की बाईस लाख छात्रों को सीधे और उसके फौरन बाद सीबीएसई परीक्षा कापी जांच की इससे कुछ ही कम छात्रों को प्रभावित करने वाली गड़बड़ियों ने, परीक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा मंत्रालय की घोर अक्षमताओं को उजागर करने के साथ ही, शिक्षा व्यवस्था के तेजी से बढ़ते संकट की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। मोदीशाही द्वारा शिक्षा के बाजारीकरण, केंद्रीकरण तथा सांप्रदायीकरण के लिए दरवाजे चौपट खोले जाने से, यह संकट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और रोजगार के बढ़ते संकट के साथ जुड़कर यह, युवाओं के भविष्य के लिए एक खौफनाक संकट का रूप ले लेता है। शिक्षा व रोजगार के जुड़वां संकट के संदर्भ में, नीट पेपर लीक के बाद से ही वामपंथी व अन्य छात्र व युवा संगठनों ने और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने भी, देश भर में अभियान छेड़ रखा था। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में भी वामपंथ के अलावा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर खासतौर पर पहल की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी इस अभियान में विशेष रूप से रुचि ले रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी इसी अभियान में से निकली थी। बहरहाल, कॉकरोच जनता पार्टी ने जब अपनी पहली मैदानी कार्रवाई के लिए इसे केंद्रीय मुद्दा बनाया, उसे सोशल मीडिया आदि डिजिटल माध्यमों से जुड़ी नयी पीढ़ी के बीच विशेष रूप से समर्थन आधार हासिल होने से, इस मुद्दे को जिस तरह देश की राजनीति के केंद्र में लाना और मोदीशाही को उसकी भारी विफलताओं के लिए घेरना संभव हुआ, इससे पहले संभव नहीं था। 20 जुलाई के संसद मार्च ने बलपूर्वक इस सच्चाई को उजागर कर दिया है और इस सच्चाई को और पुख्ता भी कर दिया है। यह संयोग ही नहीं है कि एक आमतौर पर सत्ता पक्ष समर्थक रुख अपनाने वाले, बहुसंस्करणीय हिंदी दैनिक ने अपनी सुर्खी में रेखांकित किया है कि, श्2012 के अभया प्रकरण के पूरे 14 साल बाद राजधानी में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। 20 जुलाई के संसद मार्च से ठीक पहले, संसद मार्च के दौरान और संसद मार्च के बाद भी, विपक्षी पार्टियों ने व्यवहार में, इस युवा उबाल का पूरी तरह से साथ देने की ही तत्परता दिखाई दी है। यहां तक कि शिक्षा के ही मुद्दे पर अपना स्वतंत्र अभियान चला रही, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के रुख में शुरूआत में कुछ हिचक दिखाई भी दे रही थी, तो वह संसद मार्च तक आते–आते कमोबेश दूर हो चुकी थी। राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी समेत, कांग्रेस के अनेक नेताओं का संसद मार्च के अगले ही दिन, युवाओं पर पुलिस के जोर–जुल्म के खिलाफ प्रधानमंत्री के आवास पर विरोध धरना देना, इसी का संकेतक है। फिर भी, जंतर–मंतर धरने के एक महीने के दौरान, सत्ताधारी संघ–भाजपा के प्रचार तंत्र ने जिस तरह विपक्ष को और खासतौर पर कांग्रेस को, इस नयी ऊर्जा के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें की हैं, विपक्षी ताकतें उन्हें अपने नुकसान की कीमत पर ही अनदेखा कर सकती हैं। परंपरागत राजनीति से भिन्नता, कॉकरोच जनता पार्टी जैसी परिघटनाओं की विशिष्ट शक्ति है, उसे अपना विरोधी बनाकर मोदीशाही के पाले में धकेलने के बजाय, विपक्ष को उसके साथ सहयोग के तरीके निकालने होंगे। तभी वह भारतीय धर्मनिरपेक्ष, जनतंत्र की रक्षा के अपने संघर्ष के साथ, इस नयी सामने आ रही युवा ऊर्जा को जोड़ सकेगा। वामपंथी पार्टियों तथा अन्य विपक्षी पार्टियों की भी पहल पर, देश के अनेक हिस्सों में 20 जुलाई के संसद मार्च के समर्थन में और उस पर पुलिस जुल्मों के खिलाफ, जो जोरदार प्रदर्शन हुए हैं, उनसे मोदीशाही को अवश्य चिंता होगी। मोदीशाही को शायद इससे भी ज्यादा चिंता इससे होगी कि 20 जुलाई के संसद मार्च के दिन, उसके संसद के गिर्द काफी बड़े इलाके में फोन–इंटरनैट–बंद करने के बावजूद, थोड़ी देरी से ही सही, उसकी पुलिस की कलंक गाथा, सारी दुनिया ने देखी है और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने विस्तार से दिखाई है, जिससे गोदी मीडिया के जरिए सच्चाई को दबाने के उसके पूरे उद्यम की उपयोगिता काफी घट जाती है। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों तक की इस ओर नजर गयी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की डिप्टी एशिया डायरेक्टर का बयान इसका गवाह है। विभिन्न देशों में इस दमन के खिलाफ उल्लेखनीय विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।

माधवन से आलिया भट्ट तक, छात्र प्रदर्शन के समर्थन में आए ये सितारे, जानिए क्या बोले ?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीट परीक्षा लीक के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर के अलावा मुंबई व अन्य शहरों में भी इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कई सितारे प्रदर्शन में पहुंचकर सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं, कुछ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर समर्थन जताया है। बीते दिन सलमान खान ने छात्रों के सपोर्ट में पोस्ट साझा किया था। अब आलिया भट्ट से माधवन तक कई सेलेब्स ने आवाज बुलंद की है। आलिया भट्ट ने आज गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने छात्रों को सपोर्ट करते हुए लिखा है, पिछले कुछ दिनों से मेरा दिल कई बार टूटा। मगर, उम्मीदों के सहारे सही भी हुआ। आज हर छात्र अपने हक के लिए डटा है। उसके अपने सपनों के अलावा परिवार की उम्मीदें हैं। वर्षों की मेहनत है। स्टूडेंट सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि उन सबके लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने उन पर भरोसा किया है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनेता आर माधवन ने भी इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करते हुए समर्थन जताया है। उन्होंने लिखा है, शशिक्षा में देश का भविष्य बदलने की ताकत होती है। हर स्टूडेंट ऐसी व्यवस्था का हकदार है, जो निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता पर आध ाारित हो। युवाओं की क्षमता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में आज मैं सभी छात्रों और अभिभावकों की चिंता और निराशा को समझता हूं। शिक्षा व्यवस्था को लोगों में विश्वास, निष्पक्षता और अवसर की भावना पैदा करनी चाहिए। कुछ लोग माधवन की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग देर से रिएक्शन के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

कमल हासन क्या बोले?

अभिनेता कमल हासन ने भी अपने एक्स अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) से पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए था। जब एक बच्चा रोया था तभी हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी।

ईशा कोप्पिकर बोलीं– दुखी महसूस कर रही हूं

अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। अभिनेत्री ने बताया कि कई लोग उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने नीट विवाद पर अब तक अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इस पर उन्होंने कहा कि वह भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हर विषय पर तुरंत बोलना ही सही तरीका नहीं होता। ईशा ने वीडियो में कहा, नमस्कार, कई फैंस मुझसे पूछ रहे थे कि मैं नीट के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूं। इसलिए मुझे लगा कि यह बताना जरूरी है कि चाहे मैं इस समय कितना भी दुखी महसूस कर रही हूं, लेकिन हर चीज पर बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना भी एक जिम्मेदारी होती है।

> विजय से हटकर रश्मिका की मेहंदी ड्रेस की बात करें तो उनके दुपट्टे में मां लक्ष्मी का चित्र बना है। भारतीय परिवारों में नई दुल्हन को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रश्मिका को मिले, इसलिए डिजाइनर ने सुंदर चित्र उनके दुपट्टे पर बनाया है।

भोलेनाथ बच्चों को शक्ति दें...युवाओं के समर्थन में हनी सिंह ने लिए बड़ा फैसला, टाल दी नए गाने की रिलीज

रैपर और सिंगर हनी सिंह ने हाल ही में अपने नए गाने मूनलाइट की रिलीज डेट 24 हुलाई 2026 घोषित की थी। इसके बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि इस गाने का टीजर मंगलवार को रिलीज किया जाएगा लेकिन मंगलवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए हनी सिंह ने ऐलान किया कि देश में युवाओं और छात्रों की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने फिलहाल टीजर की रिलीज कुछ समय में लिए स्थगित करने का फैसला किया है। हालांकि हनी सिंह ने अपने पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का सीध ो तौर पर कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि देश के युवाओं का सम्मान करते हुए वह अपने नए गाने मूनलाइट के टीजर की रिलीज कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए लिखा कि भोलेनाथ सभी बच्चों को शक्ति दें और अंत में जय हिन्द लिखकर अपना सन्देश समाप्त किया। अपने नए गाने मूनलाइट के टीजर को स्थगित करने की जानकारी देने से पहले हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत के युवा अमर हैं। हर–हर महादेव। उनके इस सन्देश को युवाओं के प्रति समर्थन के रूप में देखा गया। वहीं, युवाओं के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेता–निर्देशक प्रकाश राज और दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी समेत कई कलाकार सोमवार को दिल्ली के जंतर–मंतर पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुए और अपना समर्थन जताया। मंगलवार को अभिनत्री प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सरकार से अपील की कि वह सोनम वांगचुक और छात्र संगठनों के साथ सकारात्मक और सार्थक संवाद शुरू करे ताकि उनकी सेहत पर और बुरा असर न पड़े। उन्होंने सोनम से अपना अनशन समाप्त करने का भी अनुरोध किया और कहा कि उनकी सेहत इस आंदोलन जितनी ही महत्वपूर्ण है। प्रीति ने लिखा कि सोनम और छात्र देश के भविष्य तथा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

किल के बाद बदल गया लोगों का नजरिया, बोले राघव जुयाल, कहा- फहाद फासिल के मैसेज पढ़कर चौंक गया था

एक वक्त था, जब ज्यादातर लोग राघव जुयाल को डांसर, एंकर या टीवी चेहरे के तौर पर जानते थे। फिर साल 2024 में आई फिल्म श्किलश। इसमें निभाए उनके किरदार ने न सिर्फ ऑडियंस को चौंकाया, बल्कि इंडस्ट्री को भी उन्हें नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। अब राघव पहली बार फिल्म श्भाई तेरा स्टार हैश में लीड हीरो बनकर बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। हालांकि, इस पूरे सफर में अगर कोई चीज उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है, तो वह माता–पिता के चेहरे पर दिखने वाला गर्व है। अमर उजाला से खास बातचीत में राघव ने अपने 16 साल लंबे संघर्ष, श्किलश के बाद बदली पहचान, मलयालम अभिनेता फहाद फासिल के मैसेज, पहली लीड फिल्म और परिवार के साथ जुड़ी भावुक यादों पर खुलकर बात की। राघव कहते हैं कि संघर्ष उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन किल के बाद पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि लोग उन्हें अलग नजर से देखने लगे हैं। जब आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो सबको प्रूव करना पड़ता है। मां–बाप को भी और इंडस्ट्री को भी। मुझे भी प्रूव करना पड़ा। किल के बाद मेरे लिए लोगों का परसेप्शन रातों–रात बदल गया। ऐसा बदलाव मैंने अपने एक्सपीरियंस में पहले कभी नहीं देखा था। कपिल शर्मा भाई ने भी मुझसे कहा था कि जो परसेप्शन चेंज तू कर रहा है, वो बहुत अलग है। टीवी इंडस्ट्री के जितने भी लोग थे, सबने फोन किया। सब कह रहे थे कि पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमने भी ये क्रैक कर दिया। वो इमोशन मेरे लिए बहुत बड़ा था।

बातचीत के दौरान जब उन कलाकारों का जिक्र आया जिन्होंने किल देखने के बाद उनसे संपर्क किया, तो राघव बिना देर किए फहाद फासिल का नाम लेते हैं। राघव मानते हैं कि उनके करियर की सबसे बड़ी ताकत टैलेंट से पहले आत्मविश्वास रहा। यही चीज मुझे मोटिवेट करती रही कि मैं हमेशा अपने ऊपर भरोसा करता रहा। इतने साल साइड में रहा, लेकिन मेरे अंदर से कभी ये चीज नहीं गई कि मुझे यही बनना है। मैं कभी मीडियोकर माइंडसेट में नहीं रहा। 16 साल बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन जब तुम अंदर से सोच लेते हो कि तुम यही हो, तो धीरे–धीरे बाहर भी वही होने लगता है। राघव अपने संघर्ष को किसी शिकायत की तरह नहीं, बल्कि सीख की तरह देखते हैं। श्लाइफ में अनफेयर चीजें होती हैं। जिंदगी कोई स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड नहीं है। लोग अनफेयर होंगे। लेकिन बैठकर शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। रिजेक्शन मिले, फिल्मों से निकाला गया। किसी एक्टर ने मना कर दिया तो काम चला गया। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये सब एक बड़ी तस्वीर के छोटे–छोटे डॉट्स थे। जिस फिल्म के लिए मैं परेशान था, वो फिल्म बनी ही नहीं। हर बार उसके बाद कुछ बड़ा मिला। राफ्टिंग में भी रैपिड्स आते हैं, लेकिन अगर नदी पार करनी है तो पैडल मारते रहना पड़ता है। मूव ऑन करना पड़ता है।

राघव बताते हैं कि जब उन्होंने टीवी छोड़कर फिल्मों पर दांव लगाया, तब यह फैसला आसान नहीं था। जब मैं देहरादून से मुंबई आया था, तब मम्मी–पापा को भी नहीं पता था कि यहां क्या होगा। उस समय उनका सपोर्ट वैसा नहीं था, क्योंकि उन्हें इस दुनिया की समझ नहीं थी। लेकिन बाद में जब मैंने टीवी छोड़ने का रिस्क लिया, तब मैं खुद हैरान था कि वो मेरे साथ खड़े रहे। पैसे भी खत्म होने लगे थे, फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज वो सबसे ज्यादा खुश हैं। रोज लोगों को बताते हैं कि फिल्म आ रही है। रिश्तेदारों को फोन करके कहते हैं– मेरा बेटा बड़े पर्दे पर आ रहा है, टिकट लेकर देखना। उनके चेहरे की खुशी देखकर लगता है कि 16 साल की मेहनत आखिर रंग ले आई।

संघर्ष और सफलता की बातें करने के बाद राघव अपनी नई फिल्म भाई तेरा स्टार है पर आते हैं। उनके मुताबिक, फिल्म का नाम भी आम बोलचाल की उसी भाषा से निकला है, जो छोटे शहरों की पहचान है। फिल्म का टाइटल भाई तेरा स्टार है है। हर शहर में हर कोई अपने लेवल का एक

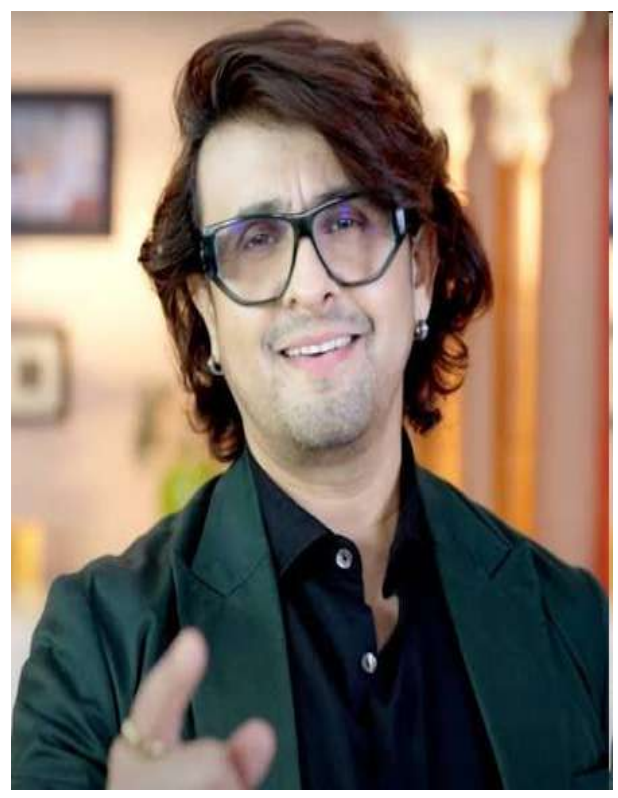

दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन पर पूछा सवाल तो भड़के सोनू निगम, बोले– मैं किसलिए आया हूं?

नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्चा लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में शुरू हुई मुहिम सोशल मीडिया से अब सड़कों पर आ चुकी है। बीते दिनों जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया गया। अब भी प्रदर्शन जारी है। कई सितारे भी छात्रों के साथ आए हैं और उनके लिए आवाज बुलंद की है। कुछ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं। हाल ही में सोनू निगम से इसे लेकर सवाल किया। जानिए उन्होंने क्या कहा? मशहूर सिंगर सोनू निगम हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे। इस दौरान उनसे कई सवाल किए गई। बातचीत के दौरान सिंगर से छात्र आंदोलन के संदर्भ में भी प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया– दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सोनू निगम ने कहा, मैं यहां किसलिए आया हूं। बस बस। जब उनसे आगे दूसरा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अभी हो गया, बस। प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंगर के रिएक्शन वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग उन्हें अनफॉलो करने की बात कर रहे हैं तो कुछ उन्हें बायकॉट करने की। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी।

महफिल लूट ले गए विजयय जन नायकन पर नेटिजंस का सीटी मार रिएक्शन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय की फिल्म जन नायकन आखिर सिनेमाघरों में सज गई है। फिल्म की थिएटर रिलीज मानो थलापति के फैंस के लिए कोई उत्सव हो। बीते दिन से ही जगह–जगह उत्साहित फैंस आयोजन करते दिखे। कोई डांस करके जश्न मना रहा है तो कोई आतिशबाजी कर रहा है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? फिल्म जन नायकन पर अधिकांश नेटिजंस ने सकारात्मक रुख दिखाया है। विजय के हाथ हिलाने वाले सिग्नेचर स्टाइल ने तो मानो महफिल ही लूट ली है। सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप वायरल हो रही हैं, जिनमें स्क्रीन पर वह सीन आते ही दर्शक सिनेमाघरों में दीवानों कि तरह चिल्ला रहे हैं। फिल्म में विजय का धमाकेदार डांस भी देखने को मिला है। एक यूजर ने सिनेमाहॉल से क्लिप शेयर करते हुए लिखा है, थलापति ने आग लगा दी। स्क्रीन पर जब विजय डांस करते दिखे, तो सिनेमाघरों में उनके फैंस भी झूमने लगे। बता दें कि यह फिल्म रिलीज से पहले लीक हो गई थी। इसके बाद फिल्म में कुछ बदलाव भी किए गए। विजय का परिचय फिल्म में मुख्यमंत्री के रूप में भी दिया गया है। सीएम वाला टाइटल कार्ड काफी वायरल हुआ है। इससे भी दिलचस्प बात है कि फिल्म से ज्यादा सिनेमाघरों का माहौल देखने लायक है। लोग समूह में जा रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। जन नायकन को लेकर नेटिजंस जहां तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं, जबर्दस्त स्क्रीन प्रेजेंस देखने लायक है। कचेरी गाने का डांस बेहतरीन है। टाइटल कार्ड, इंट्रो, इंटरवल, फ्लैशबैक और स्कूल वाला सीन सुपर हैं। विलेन का ट्रैक और क्लाइमैक्स कमजोर हैं। भले ही कुछ चीजें अजीब और इमोशन–लेस हों, लेकिन थलापति के मोमेंट्स इसे एक देखने लायक एंटरटेनर बनाते हैं। वहीं, एक यूजर ने लिखा है, श्विजय के फैंस के लिए जन नायकन फिल्म झेलने लायक है, इसलिए दूसरों के लिए तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है।

स्लिम और फिट रहने के लिए इस रूटीन का करें पालन!

आज कल पतले रहना बेहद मुश्किल है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्लिम और फिट रहें तो उसके लिए आपको स्वस्थ रूटीन का पालन करना चाहिए। यहां हमने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दी हैं जिन्हें आप भी अपनी जीवनशैली में जरूर अपनाएं –

1. प्रातःकाल की व्यायाम

रोजाना सुबह उठकर कम से कम 30–45 मिनट की व्यायाम करें। यह दौड़ना, योग या गहरी श्वासायाम हो सकती है।

2. समय पर नाश्ता

सुबह का नाश्ता समय पर करें, जिसमें प्रोटीन और फाइबर युक्त आहार शामिल हो।

3. पानी पिएं

दिन भर में नियमित अंतरालों में पानी पिएं, कम से कम 8–10 गिलास।

4. फल और सब्जी खाएं

अपने भोजन में फल और सब्जियों को शामिल करें, जो कम कैलोरी वाले और पौष्टिक हों।

5. संतुलित भोजन

मीठे और तली हुई चीजें को कम करें, और उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लें।

6. रात का भोजन

रात का भोजन हल्का होना चाहिए, और खाने के बाद अधिक से अधिक दो घंटे का विश्राम लें।

7. नियमित व्यायाम

हफ्ते में कम से कम 5 दिन व्यायाम करें, जैसे चलना, जिम या योगा।

इस रूटीन को अपनाकर आप स्वस्थ और फिट रह सकते हैं।

सावन के व्रत के दौरान ओवरईटिंग, भूखा रहना और अन्य गलतियां करने से बचें

इस साल सावन का शुभ महीना 22 जुलाई से शुरू हुआ है। हर साल सावन का महीना भक्तों द्वारा बहुत श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। यह शुभ महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस वर्ष, सावन का महीना 29 दिनों तक मनाया जाएगा और यह 19 अगस्त को समाप्त होगा। सावन सोमवार इस महीने के दौरान पड़ने वाले सोमवार हैं, भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इन शुभ सोमवारों पर व्रत रखते हैं। इस माह में शुभ घटनाएं भी देखी जाती हैं। इस साल का पहला सावन सोमवार आज (22 जुलाई) है। सावन का हर सोमवार विशेष और शुभ होता है। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और शिव लिंग को दूध, शहद और जल समर्पित करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। भक्त भगवान शिव मंत्रों का भी पाठ करते हैं और समुद्र मंथन की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले घातक जहर को पीकर सभी को बचाया। जैसा कि हम इस वर्ष के पहले सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, यहां कुछ गलतियां हैं जिनसे हमें स्वस्थ रहने के लिए बचना चाहिए।

प्याज और लहसुन

सावन के इस महीने में सभी प्रकार के तामसिक खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। प्याज, लहसुन, अंडे और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों से सख्ती से बचना चाहिए।

तले हुए खाद्य पदार्थ

उपवास शरीर को डिटॉक्सीफाई करने और पाचन तंत्र को बढ़ावा देने में मदद करता है। जब हम नमकीन और अन्य स्नैक्स जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे हम कमजोर और अयोग्य हो सकते हैं।

ज्यादा चीनी का सेवन न करें

जब हम व्रत रखते हैं तो शरीर में चीनी की चाहत होना स्वाभाविक है। सावन सोमवार का व्रत रखते समय चीनी का सेवन प्रतिबंधित नहीं है। हालांकि, उपवास रखते समय बहुत अधिक चीनी का सेवन करने से शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं।

ओवरईटिंग

हालांकि व्रत तोड़ने और खाने के बाद भूख लगना हमारे लिए स्वाभाविक है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम ज्यादा खाना न खा लें। इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सावन का महीना शांति, भक्ति और शांति का पालन करने का है। बीमार पड़ने से हमारा ध्यान बर्बाद हो सकता है।

भूखे न रहे

उपवास करना और भूखा रहना बिल्कुल अलग है। यह एक आम सोच है कि व्रत रखने के लिए हमें शरीर को भूखा रखना होगा। हालांकि, सच्चाई यह है कि उपवास करते समय हमें शरीर को फिट और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने चाहिए।

मानसून में बढ़ जाती है फूड पॉइजनिंग, इस रह पहचानकर करें बचाव

मानसून के मौसम में फूड पॉइजनिंग की बढ़ती संभावना एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। यह वक्त गर्मी से बारिशों तक का है, जब खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना अधिक मुश्किल होता है। मानसून के दौरान बढ़ती हुमीडिटी, भिगोने वाले और भिगो रहे मौसम, और खाद्य पदार्थों के संचयन और प्रसंस्करण की कठिनाई के कारण, बैक्टीरिया और अन्य कीटाणुओं का विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में, अप्रत्याशित भोजन, अस्वच्छता, और गलत संचयन के कारण खाद्य संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या से बचाव के लिए, स्वच्छता बनाए रखना, खाद्य पदार्थों को अच्छे से पकाना, शुद्ध पानी का उपयोग करना, और खाद्य संचयन के नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन सावधानियों का पालन करने से खाद्य संक्रमण की संभावना को कम किया जा सकता है और व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है।

इस वजह से होती है ये समस्या

नमी

मानसून के मौसम में वातावरण बहुत ही गीला और नमी भरा होता है, जिससे भोजन पदार्थों पर बैक्टीरिया और फंगस का विकास तेजी से होता है।

पानी का प्रदूषण

भारी बारिश से पानी के स्रोतों में प्रदूषण हो सकता है, जो खाद्य पदार्थों को प्रभावित कर सकता है। प्रदूषित पानी का उपयोग भोजन की तैयारी में या सीधे सेवन में खाद्य संक्रमण का कारण बन सकता है।

अच्छी स्वच्छता और हाथों का धोना

बारिश के कारण किचन और खाद्य संभालने के स्थानों में अच्छी स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे बैक्टीरिया का प्रसार बढ़ सकता है।

अच्छी स्वास्थ्य देखभाल

लक्षण

पेट दर्द

उल्टी

उबकाई

दस्त

बुखार

सिरदर्द

थकावट

बचाव

1. स्वच्छता खाने के तैयारी में स्वच्छता बरतें, हाथों को बार–बार धोएं।

2. सही प्रकार से पकाना भोजन को अच्छे से पकाएं, विशेष रूप से मांस, अंडे और समुद्री खाद्य पदार्थों को।

3. शुद्ध पानी प्राकृतिक और शुद्ध पानी का उपयोग करें, खाने के लिए उपयुक्त बिलकुल साफ पानी का उपयोग करें।

4. ठंडा संचयन खाद्य पदार्थों को सही तरीके से संचित करें, फ्रिज में रखें जब तक वे उपयोग हों।

5. बच्चों और अन्य पदार्थों से दूर रहें अनावश्यक संपर्क से बचें, जैसे कि अनाज, खाद्य उत्पादों, या अन्य संक्रमित वस्तुओं से।

6. बचाव में अपने अस्पताल जाएंरू एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

इन 3 बीमारियों को दूर कर सकता है आम, जानिए इसके फायदे

मीठा, रसीला और स्वाद में सबसे आगे आम को यूं ही फलों का राजा नहीं कहा जाता। यह न केवल खाने में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। हर साल 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को आम के सेहत से जुड़े फायदों के बारे में बताया जा सके और इस स्वादिष्ट फल की अहमियत को समझा जा सके। आम में विटामिन ए, सी, बी6, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। यही वजह है कि यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है।

कब्ज की समस्या दूर करता है आम

जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए आम बहुत फायदेमंद होता है। आम में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इससे मल को बाहर निकालना आसान हो जाता है। रोजाना एक आम खाने से पेट साफ रहता है और गैस, अपच जैसी समस्याएं भी नहीं होतीं।

इम्यूनिटी कमजोर है? तो आम खाइए

अगर आपको बार–बार सर्दी, जुकाम या अन्य बीमारियां होती हैं, तो समझिए आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। आम में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इससे शरीर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में सक्षम बनता है।

ब्लड प्रेशर को करता है कंट्रोल

आजकल हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी बहुत आम हो गई है। आम में पोटैशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करता है। यह दिल की सेहत को भी बेहतर बनाता है और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से दूर रखता है।

रोज आम खाने से क्या–क्या फायदा होता है?

दिल की सेहत अच्छी रहती है।

त्वचा निखरती है और चेहरे पर चमक आती है।

पाचन तंत्र मजबूत होता है और भूख भी अच्छी लगती है।

आंखों की रोशनी बढ़ती है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है।

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है।

वजन नियंत्रित रखने में भी आम मददगार हो सकता है।

ब्लड शुगर लेवल को भी सही मात्रा में खाने पर कंट्रोल में रख सकता है।

रोज कितने आम खाने चाहिए?

एक दिन में 1 या 2 मध्यम आकार के आम खाना फायदेमंद है। ध्यान रखें अत्यधिक मात्रा में कोई भी चीज सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। चाहे आम कितना भी पसंद हो, सीमित मात्रा में ही खाएं। नेशनल मैंगो डे के मौके पर हमें इस स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर फल की अहमियत को समझना चाहिए। अगर आम को सही मात्रा में रोजाना अपनी डाइट में शामिल किया जाए, तो यह आपकी सेहत को कई तरह से सुधार सकता है फिर चाहे बात हो कब्ज की, इम्यूनिटी की या दिल की सेहत की।

शाम के समय घर मे ना करें ये 5 काम, वरना आ सकती है सुख–समृद्धि में रुकावट

हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र का बहुत महत्व है। यह शास्त्र हमारे घर, कामकाजी जगह, और दैनिक जीवन के हर पहलू में असर डालता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हर समय का अपना महत्व है और हमें समय के अनुसार कुछ चीजों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शाम के समय किन पांच चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि यह घर में दरिद्रता का कारण बन सकती हैं।

शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए

शाम के समय घर में झाड़ू लगाना वास्तु शास्त्र के अनुसार गलत माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी को नाराज कर सकता है और घर में दरिद्रता का प्रवेश कर सकता है। इसलिए शाम के समय घर में सफाई करते समय झाड़ू न लगाएं। यह मान्यता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में धन की कमी हो सकती है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं।

शाम को फल या फूल नहीं तोड़ना चाहिए

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के समय फल और फूल तोड़ने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसके अलावा, यह भी माना जाता है कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ यह समय होता है, और इस समय यह कार्य करने से उनके आशीर्वाद में कमी आ सकती है।

शाम को उधार देना या लेना नहीं चाहिए

वास्तु शास्त्र में यह भी कहा गया है कि सूर्यास्त के समय पैसे उधार देना या लेना घर में क्लेश और तंगी ला सकता है। यह कार्य रात के समय करना शुभ माना जाता है। अगर आप शाम के समय पैसे उधार लेते या देते हैं तो भविष्य में उधारी चुकता करने में दिक्कत हो सकती है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं।

तुलसी के पत्ते शाम के समय नहीं तोड़ने चाहिए

तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना मना है। इससे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और इसके कारण घर में आर्थिक तंगी और अन्य परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए, शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए।

मुख्य द्वार बंद नहीं रखना चाहिए

वास्तु शास्त्र में यह कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार हमेशा खुले रखना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी माता का घर में प्रवेश मुख्य द्वार से होता है। अगर आप सूर्यास्त के समय घर का मुख्य द्वार बंद रखते हैं, तो लक्ष्मी माता का आगमन रुक सकता है, जिससे घर में धन की कमी हो सकती है।

क्लेश और झगड़े से बचना चाहिए

शाम के समय घर में किसी भी प्रकार का विवाद, क्लेश या झगड़ा नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से घर की सुख–शांति भंग होती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के माहौल को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी का वास बना रहे और घर में खुशहाली बनी रहे।

किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए

यदि शाम के समय आपके घर पर कोई व्यक्ति कुछ मांगने आए, तो उसे खाली हाथ वापस भेजना नहीं चाहिए। यह वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी को शाम के समय खाली हाथ भेजते हैं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसलिए, इस समय किसी को खाली हाथ न भेजें और उनके साथ सहानुभूति दिखाएं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप शाम के समय अपने घर को और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के इन सरल नियमों को अपनाकर आप अपने घर में सुख–शांति और समृद्धि ला सकते हैं।

संक्षिप्त

आईडीबीआई बैंक का 53,000 करोड़ रुपये का विनिवेश, फेयरफैक्स बनेगा नया मालिक

नई दिल्ली,एजेंसी। आईडीबीआई बैंक का विनिवेश अब अंतिम चरण में है। सरकार और एलआईसी बैंक में 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। कनाडाई निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंसियल होल्डिंग्स यह सौदा कर रही है। द बोनस की एक रिपोर्ट के अनुसार यह सौदा लगभग 53,000 करोड़ रुपये का है। प्रति शेयर कीमत करीब 81 रुपये तय की गई है। यह भारतीय बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक है। आईडीबीआई बैंक की शुरुआत 1964 में एक विकास वित्तीय संस्था के रूप में हुई थी। यह 2004 में एक वाणिज्यिक बैंक बना, पर 2010 के बाद खराब ऋण संकट में फंसा। वर्ष 2018 में इसका सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) 28 फीसदी तक पहुंच गया था। एलआईसी ने 2019 में 51 फीसदी नियंत्रक हिस्सेदारी लेकर बैंक को बचाया। बैंक की वित्तीय स्थिति में अब बड़ा सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2026 में शुद्ध लाभ 9513 करोड़ रुपये रहा, जो 2025 से 27 फीसदी अधिक है। सकल एनपीए घटकर 2.32 फीसदी और शुद्ध एनपीए 0. 15 फीसदी पर आ गया है। मंत्रिमंडल ने मई 2021 में विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अक्तूबर 2022 में सरकार और एलआईसी ने रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की। मार्च 2026 में कम बोलियों के कारण यह सौदा अटक गया था। जुलाई 2026 में फेयरफैक्स के संशोधित प्रस्ताव के बाद सौदा फिर सक्रिय हुआ। सरकार को इस विनिवेश से करीब 26,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। यह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का संकेत भी देता है। सरकार अब स्थायी मालिक नहीं रहना चाहती है। फेयरफैक्स को एक बड़ा बैंकिंग मंच, स्वच्छ परिसंपत्ति गुणवत्ता और मजबूत पूंजी आधार मिलेगा। बाजार अभी भी सौदे के अंतिम समापन और नई प्रबंधन योजनाओं पर नजर रखेगा।

इटर्नल लिमिटेड का मुनाफा चार गुना बढ़ा, शेयर चार फीसदी से अधिक उछल

नई दिल्ली,एजेंसी। जोमैटो और ब्लिंकिट जैसे कारोबार चलाने वाली ईटर्नल लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को 4 फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की गई। कंपनी ने जून तिमाही में अपने समेकित मुनाफे में लगभग चार गुना वृद्धि की सूचना दी है। त्वरित वाणिज्य खंड में मजबूत राजस्व वृद्धि के कारण यह उछाल देखा गया। बुधवार को ईटर्नल लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 92 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 25 करोड़ रुपये के समेकित शुद्ध मुनाफे से काफी अधिक है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में यह जानकारी दी है। इस तरह मुनाफे में करीब चार गुना की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में परिचालन से समेकित राजस्व 20,211 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की समान अवधि के 7,167 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। रिपोर्टिंग तिमाही में कुल खर्च भी बढ़कर 20,314 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 7,433 करोड़ रुपये था। गुरुवार को बीएसई पर ईटर्नल लिमिटेड का शेयर 4.28 फीसदी उछलकर 295.55 रुपये पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर भी इसमें 3.88 फीसदी की वृद्धि देखी गई। एनएसई पर शेयर 295.45 रुपये पर पहुंच गया। निवेशकों ने कंपनी के मजबूत वित्तीय परिणामों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। यह उछाल कंपनी के त्वरित वाणिज्य कारोबार में आई तेजी का सीधा परिणाम है। बाजार में कंपनी के प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अक्षत गोयल ने बताया कि जोमैटो के खाद्य वितरण कारोबार के शुद्ध ऑर्डर मूल्य (एनओवी) में 20 फीसदी से अधिक की साल–दर–साल वृद्धि हुई। यह चार लगातार तिमाहियों की तेजी के बाद 10,769 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। त्वरित वाणिज्य ब्लिंकिट का एनओवी 86 फीसदी बढ़कर 17,132 करोड़ रुपये हो गया। इन दोनों प्रमुख कारोबारों ने कंपनी के राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अक्षत गोयल ने आगे बताया कि श्गोइंग–आउटश कारोबार श्डिस्ट्रिक्टश के एनओवी में भी तेजी आई है। इसकी वृद्धि दर 60 फीसदी रही और यह 3,218 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इन सभी खंडों में मजबूत प्रदर्शन ने कंपनी के समग्र राजस्व और मुनाफे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह दर्शाता है कि कंपनी के विभिन्न कारोबार अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और भविष्य के लिए मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी एनटीपीसी ग्रीन ने अपने नतीजे जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी ने समेकित शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 38: की वृद्धि की जानकारी दी। कंपनी ने इस दौरान 305 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। नतीजों के बाद गुरुवार को कंपनी के शेयरों में 9: से अधिक की तेजी आई। कारोबार में भारी उछाल के बीच कंपनी के शेयरों का भाव गुरुवार को 99. 60 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गई। यह एक महीने से अधिक का उच्चतम स्तर है। कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज 220 करोड़ रुपये से 34: अधिक है, जबकि पिछली तीन महीनों में दर्ज 197 करोड़ रुपये से इसमें लगभग 55प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि हुई है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पदक क्यों घट सकते हैं? 2022 में जीते थे 61 मेडल, इस बार 30 मुश्किल

ग्लास्गो,एजेंसी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए 2022 जैसा प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं होगा। इस बार खेलों की संख्या 19 से घटाकर 10 कर दी गई है, जिससे भारत के कई मजबूत खेल बाहर हो गए हैं। ऐसे में पदकों की संख्या घट सकती है, हालांकि एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग से अब भी बड़ी उम्मीदें हैं। फुटबॉल विश्व कप खत्म होते ही अब खेल प्रेमियों की नजरें स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पर हैं। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले इन खेलों में भारत के 125 से अधिक खिलाड़ी और पैरा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार बर्मिंघम 2022 में भारत ने 61 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी भारत वैसा ही प्रदर्शन दोहरा पाएगा? इसका जवाब आसान नहीं है। 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 पदक अपने नाम किए थे। इनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के कुल पदकों की संख्या 564 हो गई, जिसमें 203 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य पदक शामिल हैं। सबसे बड़ी वजह है खेलों की संख्या में भारी कटौती। बर्मिंघम 2022 में 19 खेल शामिल थे, जबकि ग्लास्गो 2026 में केवल 10 खेल होंगे। यानी नौ खेलों को इस बार कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। इनमें बैडमिंटन, कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वैश, ट्रायथलॉन, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन्स जैसे खेल शामिल हैं। यही वे खेल हैं, जिनमें भारत हर बार बड़ी संख्या में पदक जीतता रहा है।

इसकी वजह आर्थिक संकट है। दरअसल, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को मिली थी। लेकिन आयोजन की लागत 6–7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंचने लगी। बढ़ते खर्च के कारण विक्टोरिया सरकार ने 2023 में मेजबानी छोड़ दी। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन पर ही संकट खड़ा हो गया। तब स्कॉटलैंड के ग्लास्गो ने कम समय में आयोजन की जिम्मेदारी ली, लेकिन साफ कहा कि वह सीमित बजट में ही गेम्स करा सकेगा। इसी वजह से खेलों की संख्या घटाकर 10 कर दी गई और पूरा आयोजन सिर्फ चार मौजूदा स्टेडियमों में रखा गया। इस बार खिलाड़ियों के लिए अलग एथलीट्स विलेज भी नहीं बनाया गया है। सभी खिलाड़ी होटल में ठहरेंगे, जबकि उद्घाटन और समापन समारोह भी पहले के मुकाबले छोटे होंगे। यानी सिर्फ इन पांच खेलों से भारत ने 28 पदक जीते थे। अगर शूटिंग को भी जोड़ लें, जो 2022 में नहीं थी लेकिन भारत का सबसे सफल कॉमनवेल्थ खेल रहा है, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में शूटिंग में सबसे ज्यादा 135 पदक जीते हैं। यही वजह है कि इस बार भारत का कुल पदक आंकड़ा काफी कम रहने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल नहीं। भले ही कई मजबूत खेल बाहर हो गए हों, लेकिन भारत अब भी कई स्पर्धाओं में मजबूत दावेदार है। सबसे ज्यादा उम्मीद एथलेटिक्स से है। भारत 32 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम के साथ उतर रहा है। ओलंपिक और विश्व चौंपियन नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड के सबसे बड़े दावेदार हैं। हालांकि उन्हें पाकिस्तान के ओलंपिक चौंपियन अरशद नदीम, श्रीलंका के रुमेश थरंगा और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स जैसी चुनौती का सामना करना होगा। इसके अलावा मुरली श्रीशंकर (लॉन्ग जंप), तेजस्विन शंकर (डेकाथलॉन), सर्वेश कुशारे (हाई जंप), प्रवीण चित्रावेल (ट्रिपल जंप) और परुल चौधरी से भी पदक की उम्मीद है। वेटलिफ्टिंग भारत के लिए फिर बड़ा पदक स्रोत बन सकती है। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू गोल्ड की सबसे बड़ी दावेदार हैं। उनके अलावा बिंदियारानी देवी, ज्ञानेश्वरी देवी और अजय बाबू जैसे खिलाड़ी भी पोडियम पर पहुंच सकते हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, विश्व चौंपियन जैसमीन लैंबोरिया और सचिन सिवाच भारत की उम्मीदें बढ़ाएंगे। जूडो में तुलिका मान, अस्मिता डे, इनुंगनबी और इशरूप नारंग से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं, लॉन बॉल्स में भारत 2022 के ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगा। पिछली बार भारत ने इस खेल में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज का मानना है कि भारत इस बार करीब 30 पदक जीत सकता है। यह संख्या 2022 के 61 पदकों से लगभग आधी होगी।

रवि शास्त्री ने किसे सौंपी कप्तानी ? गंभीर–जहीर और एंडरसन को जगह नहीं

मुंबई,एजेंसी। भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलाकर अपनी ऑलटाइम वनडे इलेवन चुनी है। शास्त्री की टीम में कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन कुछ फैसलों ने क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान भी किया है। उन्होंने टीम की कमान पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी है, जबकि इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को जगह नहीं दी। स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत में रवि शास्त्री ने अपनी पसंदीदा भारत–इंग्लैंड संयुक्त वनडे टीम का चयन किया। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को चुना। सचिन का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में शानदार रिकॉर्ड रहा है। वहीं रोहित शर्मा ने हाल ही में लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे में 138 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी दावेदारी और मजबूत की थी। शास्त्री का सबसे चौंकाने वाला फैसला बल्लेबाजी क्रम में देखने को मिला। उन्होंने जोस बटलर को नंबर–तीन पर रखा, जबकि विराट कोहली को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुना। इसके बाद बाएं हाथ के पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को पांचवें स्थान पर जगह दी गई, जिनका इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन हमेशा प्रभावशाली रहा है। ऑलराउंडर के तौर पर रवि शास्त्री ने भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव और इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी बेन स्टोक्स को चुना।

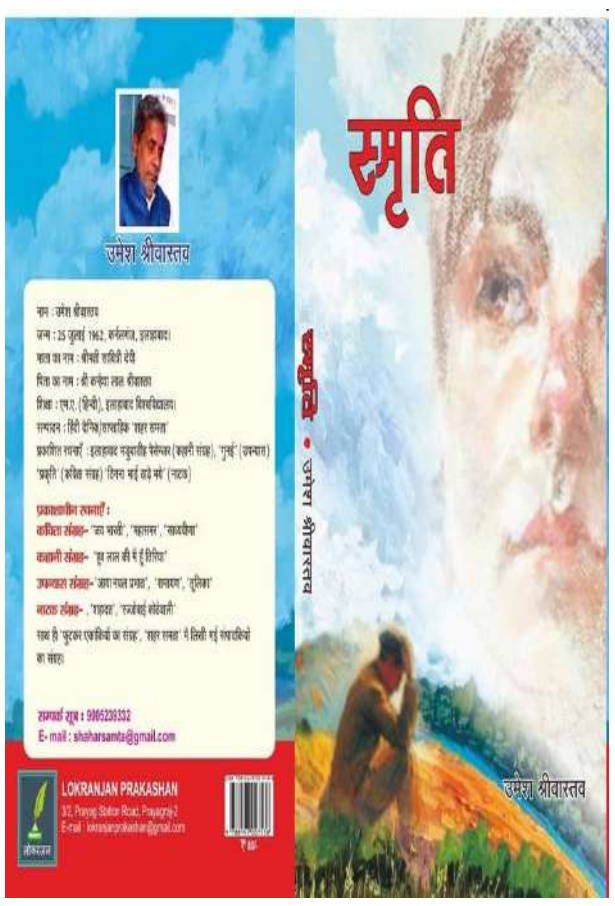

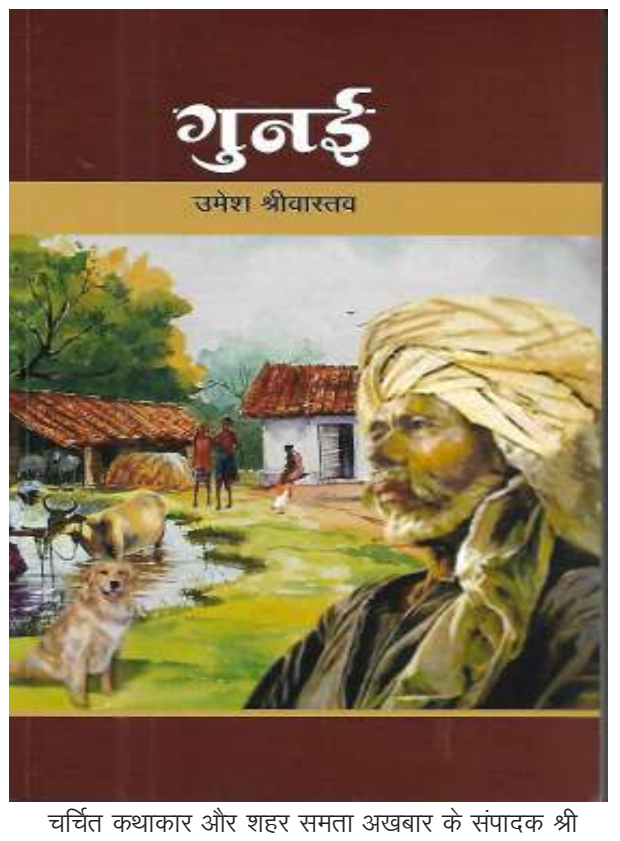

चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित

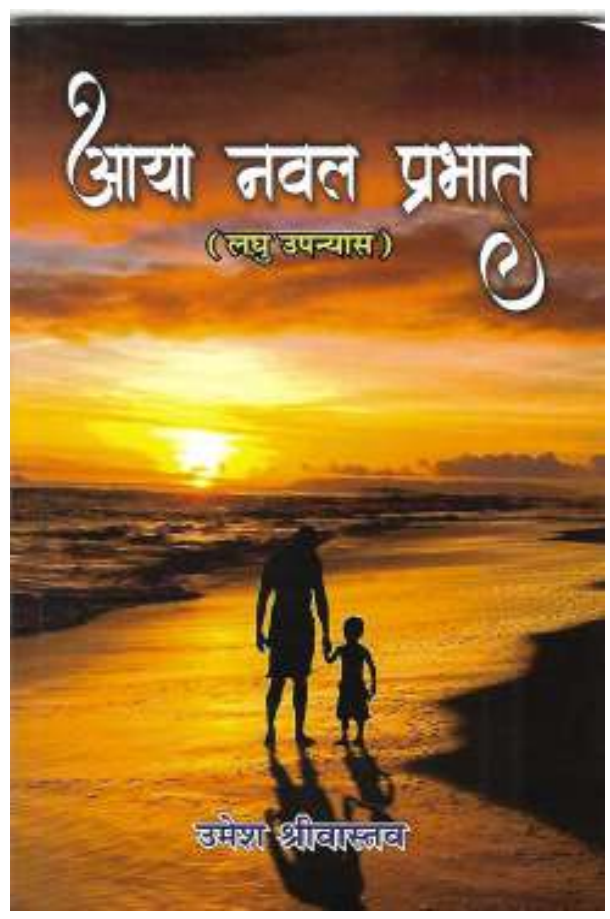

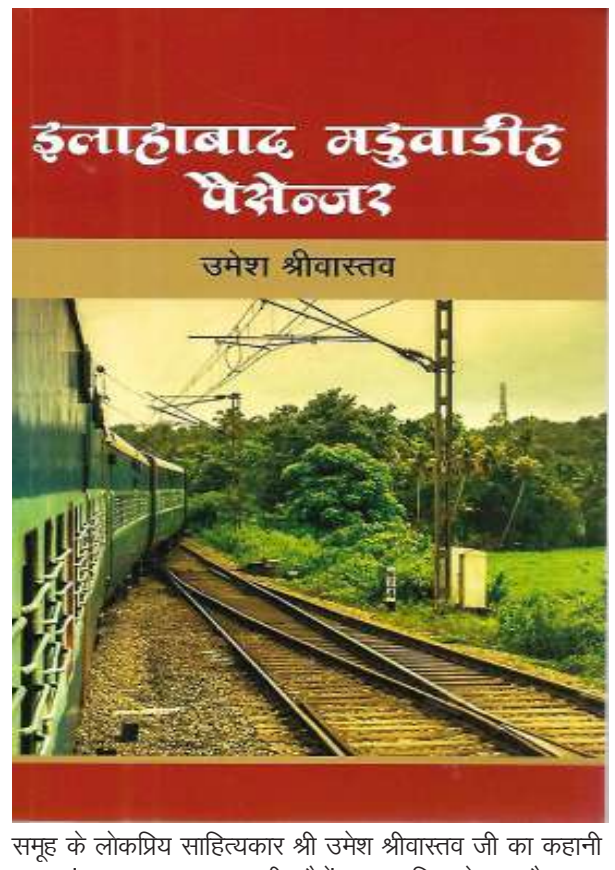

समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।

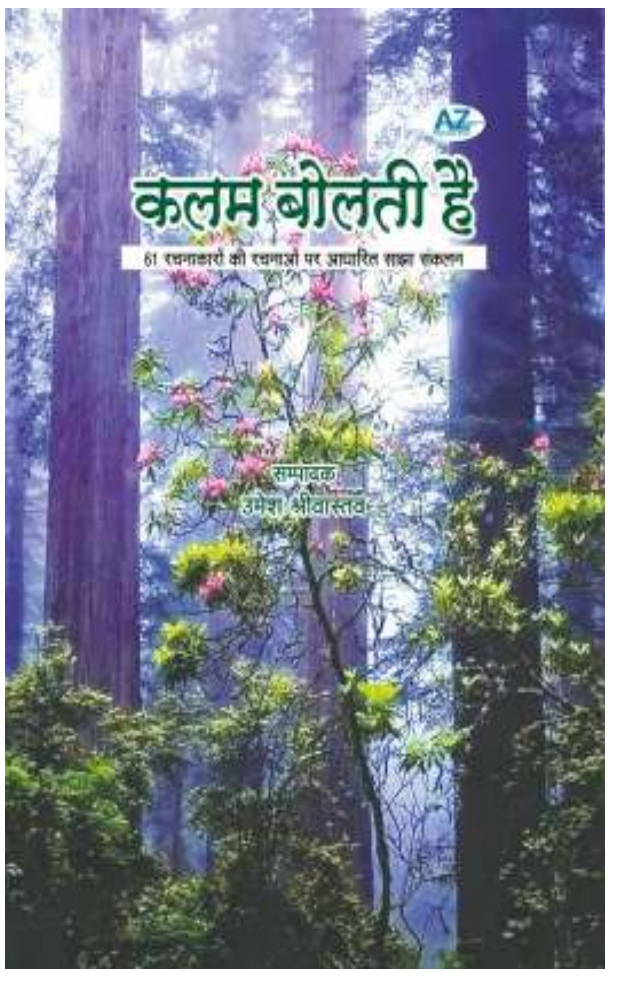

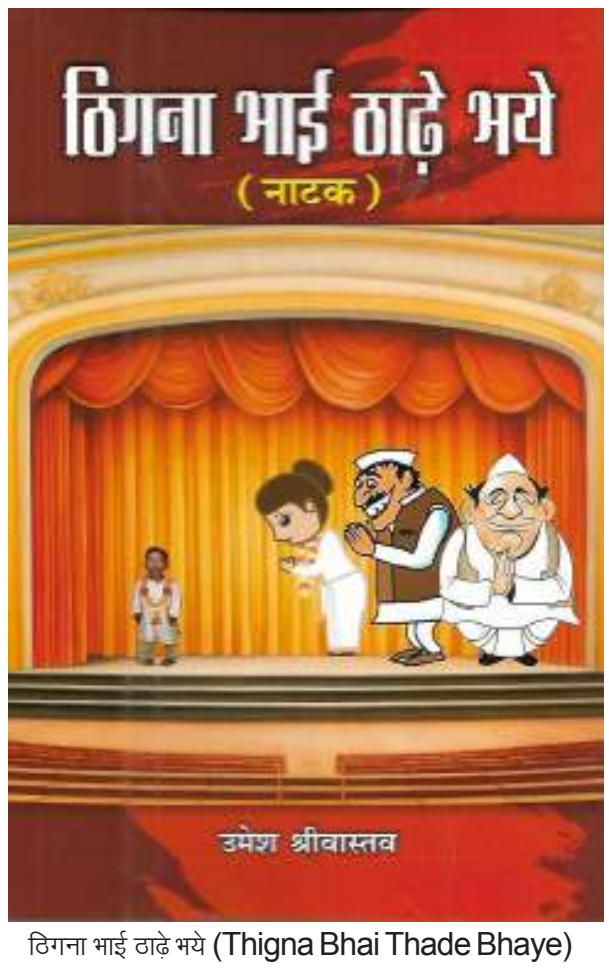

ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

संक्षिप्त

आसियान में रुबियो-लावरोव की अहम मुलाकात आज, यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर फिर होगी बातचीत?

मनीला, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो गुरुवार को फिलीपींस में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करने वाले हैं, जहां उनसे यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की ओर से मध्यस्थता करने की संभावना को

फिर से उठाने की उम्मीद है। कहां होगी बैठक? रुबियो और लावरोव के बीच यह बैठक दक्षिण–पूर्व एशियाई विदेश मंत्रियों की एक बैठक के दौरान होने वाली है, जो मनीला में आयोजित दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के आयोजन में क्षेत्र के शीर्ष राजनयिकों की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। रूस–यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के मध्यस्थता के प्रयास मंद पड़ गए हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष वार्ताएं रुक गई हैं। ईरान युद्ध मुख्य मुद्दा बन गया है। अंतरिम युद्धविराम समझौते के विफल होने के बाद वाशिंगटन और तेहरान द्वारा नए सिरे से हमले तेज हो गए हैं। रुबियो ने क्या कहा?

रुबियो ने बुधवार को मनीला में पत्रकारों से कहा कि वह लावरोव के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का मुद्दा उठाने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि अमेरिका इस संघर्ष को समाप्त करने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है अगर ऐसा अवसर मिलता है। रुबियो ने रूस को लेकर क्या कहा? उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ महीनों में इन प्रयासों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या बातचीत को फिर से शुरू करने का कोई अवसर है। रुबियो ने कहा, श्हमें रूसी सरकार के साथ संबंध बनाए रखने होंगे, भले ही हमारे बीच कुछ क्षेत्रों में असहमति हो।श उन्होंने यह भी जिक्र किया कि वे दो सबसे बड़े परमाणु–सशस्त्र देश हैं। आसियान की बैठक में पत्रकारों से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन हालिया बयानों के बारे में रूबियो से पूछेंगे जिनमें उन्होंने भविष्यवाणी की है कि समझौता होने वाला है। लावरोव ने कहा, श्मैं कल मार्को रुबियो से इस बारे में पूछूंगा। युद्ध समाप्त करने के लिए नए सिरे से बातचीत शुरू होने की उम्मीदें ऐसे समय में जगी हैं जब यूक्रेन ने इस वर्ष महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन रक्षा नेताओं के बीच मतभेद ने उसके प्रयासों को पटरी से उतारने की धमकी दी है। राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों सहित सरकार में व्यापक फेरबदल किया है। जयशंकर से भी मुलाकात की

रुबियो ने बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ लंबी बैठक की और अलग से भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से भी मुलाकात की। रुबियो ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने और वांग ने दक्षिण चीन सागर में विवादित चट्टानी क्षेत्र में चीनी और फिलिपिनो सेनाओं के बीच इस सप्ताह हुई नई झड़प पर चर्चा की, जिस पर बीजिंग लगभग पूरी तरह से अपना दावा करता है। रुबियो ने इस घटना को विघटनकारी बताया।

ईरान ने परमाणु ठिकाना बदला, यूएस ने सऊदी के साथ की न्यूक्लियर डील, क्या खाड़ी में अब परमाणु युद्ध तय?

वॉशिगंटन, एजेंसी। अमेरिका–ईरान के बीच तकरीबन चार महीने से युद्ध जारी है। इस संघर्ष में बीच में एक दौर संघर्ष विराम का भी आया, जब दोनों ही देश कुछ शर्तों के साथ युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए। इस अंतरिम समझौते में एक शर्त ईरान के परमाणु संवर्धन को आगे न बढ़ाने की थी। हालांकि, न तो शांति का यह दौर ज्यादा दिन नहीं चला और न ही युद्ध रोकने की शर्तों पर ही दोनों देश कायम रह सके। इस बीच सामने आया है कि ईरान ने अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को पूर्व के ठिकानों से हटाकर एक नई पहाड़ी शृंखला पिकैक्स में शिफ्ट कर दिया है। खबर है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने कुछ परमाणु ठिकानों में मौजूद परमाणु संवर्धन के लिए जरूरी सेंट्रीफ्यूजेस को इस पहाड़ी में पहुंचा दिया है। इसके अलावा एक और खबर ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। यह खबर है अमेरिका के अचानक सऊदी अरब से परमाणु संवर्धन के समझौते को उच्चस्तरीय मंजूरी देने की। कई विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई है कि जो अमेरिका पहले ईरान को परमाणु संवर्धन से रोक रहा था, वही अब पश्चिम एशिया में एक और देश की परमाणु संवर्धन में मदद करने जा रहा है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान ने अपनी परमाणु संवर्धन योजना में क्या बदलाव किया है और यह इस वक्त क्यों किया गया है? क्या ईरानी सुरक्षाबल अमेरिका से संघर्ष की अपनी नीति बदलने की तैयारी कर रहे हैं? इसके अलावा अमेरिका की तरफ से हाल ही में सऊदी से जो परमाणु समझौता किया गया है, उसका सार क्या है? क्या इससे पश्चिम एशिया में शक्ति का संतुलन बदलने की कोशिश की जा रही है? आइये जानते हैं... विशेषज्ञों के मुताबिक, इस नई भूमिगत सुविधा का उपयोग यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज के निर्माण के लिए किया जा सकता है, ताकि ईरान पहाड़ की सुरक्षा के अंदर तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर सके। वैसे तो यह केंद्र अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संदेह जताया है कि ईरान ने वहां अपने सेंट्रीफ्यूज स्थानांतरित कर चुका है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ईरान के पिछले सेंट्रीफ्यूज कार्यक्रम को अमेरिकी–इस्राइली हमलों में जबरदस्त नुकसान हुआ था।

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र
शहर समता हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र
मोबाईल नम्बर 9190052 39332
919450482227

बंधुआ मजदूरी से उत्पाद पर आज आएगी अमेरिकी रिपोर्ट, जद में भारत समेत कितने देश ?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका भारत सहित अपने 60 व्यापारिक साझेदार देशों में बंधुआ मजदूरी से तैयार उत्पाद के संबंध में गुरुवार को अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट जारी करेगा। अमेरिका ने इन देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच की थी। यह कदम सभी देशों पर लगाए गए 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ की समय–सीमा समाप्त होने से ठीक पहले उठाया जा रहा है। भारत ने इस जांच का विरोध करते हुए कहा था कि इन मुद्दों पर द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत ही चर्चा की जा सकती है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने क्या कहा?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर ने सीनेट वित्त समिति को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के शीर्ष 60 व्यापारिक साझेदारों की ओर से अपनी सीमाओं पर बंधुआ मजदूरी से तैयार सामानों के आयात पर रोक न लगाने या उसे प्रभावी ढंग से लागू न कर पाने की जांच की गई थी। पिछले महीने यूएसटीआर ने देशों के मौजूदा उपायों की कड़ाई के आधार पर 10 फीसदी और 12.5 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया था। ग्रीर ने बताया कि यूएसटीआर को इस पर 1,600 से अधिक आपत्तियां–टिप्पणियां मिली हैं और 107 गवाहों के साथ दूसरे दौर की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। भारत ने जांच पर जताई आपत्ति, दूसरे देशों की भी जांच जारी भारत ने अमेरिका की इस जांच का विरोध किया है। भारत का कहना है कि इस तरह के मुद्दों पर एकतरफा कार्रवाई करने के बजाय इन्हें भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर फिलहाल बातचीत चल रही है। यूएसटीआर ने यह भी बताया कि अमेरिका एक दर्जन से अधिक देशों में अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन क्षमता की भी जांच कर रहा है। हालांकि, इस मामले में अभी शुरुआती निष्कर्ष जारी नहीं किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने यह जांच उस समय शुरू की थी, जब फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगाए गए पारस्परिक शुल्क को अवैध करार दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, जिसकी अवधि शुक्रवार को खत्म हो रही है। अमेरिका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार लगभग 141 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत का निर्यात 87.3 अरब डॉलर था। सीनेट की सुनवाई के दौरान सीनेटर जॉन बरासो ने भारत में अमेरिकी सोडा ऐश (वकं ाी) उत्पादकों को बाजार तक उचित पहुंच मिलने का मुद्दा उठाया। इस पर ग्रीर ने कहा कि उनकी भारत के व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों से अच्छी बातचीत होती है और वह अगली बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की भी अमेरिका की तरह व्यापारिक जांच और राहत संबंधी प्रक्रियाएं हैं और अमेरिका चाहता है कि वहां अमेरिकी कंपनियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। भारत ने 16 मार्च 2026 को दुनिया के कई देशों से आने वाले सोडा ऐश के आयात पर एंटी–डंपिंग जांच शुरू की थी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि सस्ते आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है या भविष्य में नुकसान की आशंका है। ट्रंप प्रशासन व्यापारिक साझेदार देशों पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है,

ऑपरेशन हार्ड बॉल: ड्रग्स तस्करी मामले में हरमनवीर सिंह गिरफ्तार, रविंदर ढांडा गैंग पर FBI ने कसा शिकंजा

वाशिंगटन, एजेंसी। एफबीआई ने कनाडा स्थित रविंदर ढांडा गिरोह के लिए मादक पदार्थों की तस्करी में कथित भूमिका के लिए भारतीय नागरिक हरमनवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। एफबीआई ने बुधवार को बताया कि सिंह को मंगलवार को कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने क्या कहा? एफबीआई की यह कार्रवाई ऑपरेशन हार्ड बॉल के बाद हुई, जो लॉरेंस बिश्नोई, जगगु भगवानपुरिया और रविंदर ढांडा की गिरोहों को लक्षित करने वाली एक समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन कार्रवाई थी। जांच एजेंसी ने कहा कि सिंह एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन में कथित संलिप्तता के

लिए वांछित था, जो प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण और वितरण के इरादे से रखने की साजिश और प्रतिबंधित पदार्थों के निर्यात की साजिश में शामिल था। रविंदर ढांडा पर क्या आरोप है?

इसमें कहा गया है कि रविंदर ढांडा संगठित अपराध समूह का मुख्यालय वैंकूवर, कनाडा में है और कथित तौर पर यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठनों के लिए बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथम्फेटामाइन की तस्करी करता था। वारंट कब जारी हुआ ? 23 जून, 2026 को, सिंह के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में एक संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, क्योंकि उन पर नियंत्रित पदार्थों के वितरण और वितरण के इरादे से कब्जे की साजिश रचने, निर्यात की साजिश रचने और वितरण के इरादे से कब्जे का आरोप लगाया गया था। अबतक कितने लोग हुए गिरफ्तार? इस महीने की शुरुआत में एक संयुक्त अभियान में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया। जिनमें से 11 कैलिफोर्निया में थे। जो भारत स्थित तीन अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों से जुड़े थे और जिन पर कई आपराधिक कृत्यों का आरोप लगाया गया था। कुल मिलाकर, अमेरिकी न्याय विभाग ने अपने श्ऑपरेशन हार्ड बॉलश के तहत अभियोग में 37 लोगों पर आरोप लगाए थे।

अमेरिका: एरिजोना में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में भारतवंशी अमीश शाह जीते, अब किससे होगा मुकाबला ?

फिनिक्स (एरिजोना), एजेंसी। भारतीय मूल के अमीश शाह ने बुधवार को एरिजोना के एक अहम कांग्रेस (संसद) क्षेत्र में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की है। यह काफी कड़ा मुकाबला था। शाह की जीत से डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमेटी (डीसीसीसी) को झटका लगा है, क्योंकि उसने शाह के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार का समर्थन किया था। यह नतीजा ऐसे समय आया है, जब ज्यादा से ज्यादा मतदाता वाशिंगटन में पार्टी नेताओं की पसंद को खारिज कर रहे हैं। आपातकालीन चिकित्सक अमीश शाह अब आम चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार जे फीली का सामना करेंगे। फीली नेशनल फुटबॉल लीग (एनएफएल) के पूर्व खिलाड़ी हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरी चुनाव में उनका समर्थन किया था। राजनीति में विरोधी बनने से पहले फीली और शाह एक ही टीम न्यूयॉर्क जेट्स का हिस्सा थे। शाह टीम के किनारे तैनात डॉक्टर थे, जबकि फीली टीम के किकर थे। डीसीसीसी ने किस उम्मीदवार का साथ दिया था? डीसीसीसी ने मार्लीन गैलन–वूड्स का समर्थन किया था। वह पहले रिपब्लिकन पार्टी में थीं और ट्रंप के पहले कार्यकाल की शुरुआत में डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गई थीं। क्यों अहम माना जा रहा था यह मुकाबला? पहले कांग्रेस क्षेत्र के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा था। इस क्षेत्र में उत्तर–पूर्वी फीनिक्स, स्कॉट्सडेल, फाउंटेन हिल्स और पैराडाइज वैली जैसे समृद्ध इलाके शामिल हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा, इसे तय करने में यह चुनाव भूमिका निभा सकता है। हालांकि, इस क्षेत्र में रिपब्लिकन मतदाता ज्यादा हैं, लेकिन पिछले एक दशक में यहां के लोगों की राजनीतिक सोच कुछ हद तक बदली है। यह सीट खाली हुई है क्योंकि रिपब्लिकन सांसद डेविड श्वाइकर्ट ने गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ा था। लेकिन मंगलवार को रिपब्लिकन प्राइमरी में वह एंडी बिग्स से हार गए। डीसीसीसी के फैसले पर क्यों उठे सवाल? डीसीसीसी के गैलन–वूड्स को समर्थन देने के फैसले से स्थानीय डेमोक्रेट्स हैरान थे। इसकी वजह यह थी कि गैलन–वूड्स और शाह की राजनीतिक सोच में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों ही बीच की राजनीतिक सोच रखने वाले उम्मीदवार हैं। यह चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़ते प्रगतिशील और मध्यमार्गी नेताओं के बीच विवाद का हिस्सा भी नहीं था। यह मुकाबला कुछ हद तक 2024 के चुनाव जैसा था। उस समय शाह ने कई उम्मीदवारों के बीच हुए प्राइमरी मुकाबले में मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। उस चुनाव में गैलन–वूड्स भी शामिल थीं। हालांकि, आम चुनाव में शाह हार गए थे। उस साल डीसीसीसी ने प्राइमरी में किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया था, लेकिन आम चुनाव में शाह का साथ दिया था। मई में जब डीसीसीसी ने गैलन–वूड्स को समर्थन देने का एलान किया, तो डीसीसीसी की अध्यक्ष और अमेरिकी सांसद सुजान डेलबेनी ने उनके टीवी पत्रकारिता के अनुभव की तारीफ की, लेकिन शाह के बारे में कुछ नहीं कहा। शाह ने मंगलवार रात समर्थकों से कहा, मैं अपनी पार्टी की पहली पसंद नहीं था। लेकिन मैं पार्टी के स्थापित नेतृत्व के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार था और यही इस क्षेत्र के मतदाता चाहते हैं। हालांकि, शाह ने कहा है कि उम्मीदवार बनने के बाद वह डीसीसीसी के साथ काम करेंगे। उन्हें चुनाव जीतने के लिए पार्टी और उसके दानदाताओं के समर्थन की जरूरत होगी, क्योंकि यह मुकाबला मुश्किल माना जा रहा है। इस क्षेत्र में 2024 में ट्रंप को मामूली जीत मिली थी। वहीं, 2020 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी से यह क्षेत्र जीता था, जबकि श्वाइकर्ट दोबारा सांसद चुने गए थे।

अमेरिका के मैडिसन में पुलिस पर फायरिंग: गिरफ्तारी के दौरान अधिकारी पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में आरोपी ढेर

वॉशिगंटन, एजेंसी। मैडिसन के एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। क्योंकि पीड़ित ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस को चाकू से घायल कर दिया था। यह जानकारी शहर के पुलिस प्रमुख ने दी। पुलिस ने क्या बताया? घटना के तुरंत बाद गोलीबारी का मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में तीन गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। मैडिसन पुलिस प्रमुख जॉन पैटरसन ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि प्रसारित हो रहा फुटेज घटना का सिर्फ एक पहलू है। पैटरसन ने कहा श्मैं इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। पैटरसन ने बताया कि मृतक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी, लेकिन पुलिस ने उसका नाम जारी नहीं किया। यह घटना कहां हुई? यह गोलीबारी राज्य की राजधानी से दो मील से भी कम दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय इलाके की सड़क पर हुई, जहां रेस्तरां, बार, दुकानें और आवासीय मकानों की भरमार है। घटना के फुटेज में चौराहे पर कई कारें रुकी हुई दिखाई दे रही हैं और लोग घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2015 में, उसी सड़क पर एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने टोनी रॉबिन्सन, जो मिश्रित नस्ल के थे उसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। जिला अटॉर्नी ने उस घटना में पुलिस के खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अधिकारी की कार्रवाई को उचित ठहराया था। बुधवार को गोली चलाने वाले अधिकारी और गोली लगने से मारे गए व्यक्ति की नस्ल के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी जारी नहीं की। लेकिन मैडिसन में अश्वेत समुदाय के समर्थकों ने कहा कि मरने वाला व्यक्ति अश्वेत था। अश्वेत समुदाय के लोगों ने क्या कहा? मैडिसन स्थित अश्वेत समुदाय के हिमायती समूह अर्बन ट्रायज की प्रमुख ब्रांडी ग्रेसन ने कहा श्मैडिसन की एक सड़क पर एक और अश्वेत व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे समुदाय ने उसका नाम जानने से पहले ही उसे मरते हुए देखा। यह राज्य हिंसा की क्रूरता है। पुलिस को क्या सूचना मिली? पैटर्सन ने बताया कि पुलिस को पड़ोस में खड़ी गाड़ियों में घुसने की कोशिश करने की सूचना मिली थी। पैटर्सन ने बताया कि संदिग्ध पुलिस अधिकारियों के सड़क पर संपर्क करने से पहले पास के पिछे से होते हुए बाइक पर भाग निकला।

अमेरिका: ट्रांसजेंडर सैनिकों के इलाज व टेस्टोस्टेरोन नीति में क्या फर्क? जज ने ट्रंप प्रशासन पर उठाए सवाल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की नई टेस्टोस्टेरोन जांच और उपचार पहल पर एक संघीय जज ने सवाल उठाए हैं। जज ने पूछा कि सैनिकों में कम टेस्टोस्टेरोन

के उपचार और ट्रांसजेंडर सैनिकों को दिए जाने वाले हार्मोन उपचार में आखिर अंतर क्या है। यह सवाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति पर चल रहे मुकदमे के दौरान उठा, जिसमें ट्रांसजेंडर सैनिकों पर रोक लगाई गई है। जज ने क्या कहा? वाशिंगटन की अमेरिकी जिला जज एना रेयेस ने कहा कि ट्रंप की नीति में लिखा है कि सशस्त्र बलों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊंचे मानकों का पालन करना चाहिए। इसके लिए नियमित इलाज या विशेष व्यवस्था पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जज ने मुकदमे से जुड़े दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे बताएं कि ट्रांसजेंडर पुरुषों और अन्य सैनिकों को टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने में चिकित्सकीय और व्यावहारिक स्तर पर क्या समानताएं और क्या अंतर हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से यह भी जानकारी मांगी कि नई टेस्टोस्टेरोन नीति और ट्रांसजेंडर सैनिकों पर रोक के बीच अलग–अलग व्यवहार का आधार क्या है। रक्षा मंत्री की नई पहल क्या है? यह आदेश उस घोषणा के एक सप्ताह बाद आया है, जिसमें रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन की कमी की जांच के लिए नया कार्यक्रम शुरू करने की बात कही थी। पीट हेगसेथ ने कहा था कि यह जरूरी है, ताकि सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकें। उन्होंने बताया था कि 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सैनिकों की हर साल होने वाली अनिवार्य स्वास्थ्य जांच के दौरान यह जांच भी की जाएगी। 30 वर्ष से कम उम्र के सैनिक अपनी इच्छा से यह जांच करा सकेंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में हेगसेथ ने कहा था कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? ट्रंप प्रशासन के दूसरे अधिकारी भी पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन उपचार को आसान बनाने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस विषय पर वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं, जिनके पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से कम होता है।

'नापाक' बोल: 'मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बना दो', नवाज शरीफ चुनावी रैली में कश्मीर का जिक्र कर और क्या बोले?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएल–एन) के प्रमुख नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी आगामी चुनाव जीतती है तो वह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्हें पीओके का प्रधानमंत्री बनाने का अनुरोध करेंगे, ताकि वह वहां के विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर सकें। नवाज शरीफ ने चुनावी रैली में क्या कहा?

प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।